● वर्ष-2
● अंक-282
रायपुर, मंगलवार
18 जुलाई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

मानसून सत्र से पहले तेज हुई 2024 की दौड़

जेपी नड्डा बोले- राजग देशहित पर आधारित है और विपक्षी दलों के गठबंधन की बुनियाद 'स्वार्थ' पर टिकी है

नईदिल्ली। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। सभी दल अपने-अपने समीकरणों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच 20 तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हालांकि, राजनीतिक दलों का पूरा का पूरा फोकस 2024 चुनाव है। 23 जून को पटना में हुए बैठक की सफलता के बाद विपक्षी दल बेंगलुरु में आज और कल बड़ी बैठक करेंगे। यह मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन होगा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने जा रही है। 18 को एनडीए की भी एक बड़ी बैठक दिल्ली में होगी। इसमें 38 दल शामिल होंगे।

विपक्षी दलों की बैठक

बेंगलुरु में आज से विपक्षी दलों की बैठक शुरू हुई है। हालांकि आज का सत्र सिर्फ मेल मिलाप का है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा रखी गई रात्रि भोज में सभी दल शामिल होंगे। कल 11:00 बजे से बड़ी बैठक शुरू होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू यादव, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी

के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन सहित तमाम विपक्ष नेता बेंगलुरु में पहुंच चुके हैं और वे सिद्धारमैया के रात्रिभोज में शामिल भी हुए हैं। विपक्ष की 26 पार्टियों के शीर्ष नेता दक्षिण भारत के इस प्रमुख शहर में इस बात को लेकर दो दिवसीय मंत्रणा करेंगे कि कैसे अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए और एकजुट होकर उसे मात दी जाए। बैठक की शुरुआत से पहले यहां पोस्टरों के माध्यम से 'हम एक हैं' (यूनाइटेड वी स्टैंड) का संदेश देने का प्रयास किया गया।

एनडीए की बैठक

भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) देशहित पर आधारित है और इसका लक्ष्य सेवा करना है, जबकि विपक्षी दलों के गठबंधन की बुनियाद 'स्वार्थ' पर टिकी है तथा उसके पास न तो कोई नेता है, न कोई नीति है और ना ही निर्णय लेने की कोई क्षमता। उन्होंने कहा कि राजग की मंगलवार शाम होने वाली बैठक में 38 दलों ने शामिल होने की पुष्टि की है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को 'भानुमति का कुनबा' करार दिया और कहा, ''ये ऐसा गठबंधन है, जिसके पास न तो नेता है और न ही नीयत है, न नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह 10 साल की संप्रग सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है।''

एनडीए की बैठक में शामिल होंगे 38 दल: जेपी नड्डा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में नड्डा ने दावा किया कि जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं, इसमें एनडीए के सभी दलों ने रूचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुशासन का काम किया गया है और हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं। अब तक 28 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थी को हस्तांतरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले नौ वर्षों में हमने पीएम मोदी का मजबूत नेतृत्व देखा है। इसे देश ने सराहा है और सकारात्मक माहौल बना है। देश का सामान्य नागरिक भी गौरव महसूस करता है। उन्होंने कहा कि बैठक को लेकर एनडीए में उत्साह है।

विपक्षी एकता में कौन	एनडीए में कौन
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	भारतीय जनता पार्टी
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	एआईएडीएमके, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट),नेशनल पीपुल्स पार्टी
जनता दल (यूनाइटेड)	नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी
शिव सेना (यूबीटी)	सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट)	जननायक जनता पार्टी, इंडिया मक्कल
राष्ट्रीय जनता दल	कालवी मुनेत्र कड़गम
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन)
जम्मू एवं कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन	रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया)
झारखंड मुक्ति मोर्चा	मिजो नेशनल फ्रंट),तमिल मनीला कांग्रेस)
मरुमलारची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम	आईपीएफटी (त्रिपुरा),
रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (भारत)	बोडो पीपुल्स पार्टी),महाराष्ट्रवादी गोमांतक
विदुथलाई चिरुथिगल काची	पार्टी)
असम जातीय परिषद	एजीपी (असम गण परिषद)
गोवा फॉरवर्ड पार्टी	राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
केरल कांग्रेस	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल)
भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी	ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पुडुचेरी)
आंचलिक गण मोर्चा	शिरोमणि अकाली दल (ढींढसा)
केरल कांग्रेस (जैकब)	जन सेना (पवन कल्याण)
राष्ट्रवादी कांग्रेस केरल	पीएमके, निषाद पार्टी, अपना दल,
भारतीय किसान एवं श्रमिक पार्टी	

इन दिनों

✍ जितेंद्र भारद्वाज

शर्त पूरी करने पर पुरानी पेंशन मिलेगी

केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज होती जा रही है। इसके लिए दोहरा मोर्चा काम कर रहा है। एक मोर्चे पर केंद्र एवं राय सरकारों के कर्मचारी संगठन हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है। इस मुद्दे पर सरकार ने वित्त मंत्रालय की एक कमेटी गठित की है। हालांकि इस कमेटी का जो कार्यक्षेत्र तय किया गया है, उसमें ओपीएस का कहीं भी जिक्र नहीं है। उसमें केवल एनपीएस में सुधार की बात कही गई है। पिछले दिनों भी सरकार ने अपने उन कर्मियों को एनपीएस से हटाकर ओपीएस में शामिल होने का अवसर प्रदान किया था, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 22 दिसंबर 2003 से पहले शुरू हुई थी, मगर उनकी ज्वाइनिंग एक जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है। अब इसी तर्ज पर अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी वन टाइम विकल्प प्रदान किया गया है। अगर वे भी उक्त शर्त को पूरा करते हैं तो उन्हें ओपीएस में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारी, जिनकी नियुक्ति किसी ऐसे पद या वैकेंसी के विरूद्ध हुई थी, जिनकी भर्ती की अधिसूचना/विज्ञापन 22 दिसंबर 2003 से पहले जारी हुआ था। किसी वजह से उनकी वाइनिंग एक जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई, तो वे पुरानी पेंशन की बजाए एनपीएस के दायरे में आ गए। ऐसे अधिकारियों को अब ओपीएस में शामिल होने के लिए वन टाइम छूट प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत वे अधिकारी आएंगे, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2003 और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2004 के जरिए सेवा में आए हैं। भारतीय वन सेवा, 2003 के अधिकारी भी वन टाइम छूट के दायरे में शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों को भी उक्त योजना का लाभ मिलेगा, जो 22 दिसंबर 2003 से पहले किसी अन्य जॉब में थे, लेकिन उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में स्थान बनाया था। यानी वे अधिकारी पहले से ही केंद्र की किसी सेवा में काम कर रहे थे। लिहाजा उस वक्त केंद्र और राय सरकारों में पुरानी पेंशन लागू थी। वे पुरानी पेंशन में शामिल हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने उक्त अवधि के दौरान यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस, आईपीएस और आईएफएस में जगह बनाई और एक जनवरी 2004 को या उसके बाद ज्वाइनिंग की, तो उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। इस मामले में कई अधिकारी और कर्मचारी, अदालतों में भी गए थे। कैट में भी यह मामला जा चुका है। वहां से कर्मियों में हक में जो फैसला आया, उसके बाद सरकार ने सभी अधिकारी और कर्मियों को वन टाइम विकल्प प्रदान करने का निर्णय लिया। डीओपीटी ने सभी रायों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा है कि उक्त शर्त पर खरे उतरने वाले अधिकारी, ओपीएस में शामिल होने के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं।

केजरीवाल की जिद पर कांग्रेस ने ली अपनों की नाराजगी

जितेंद्र भारद्वाज

विपक्षी दलों की दो दिवसीय बैठक बेंगलुरु में सोमवार से शुरू हो रही है। सोनिया गांधी सहित 26 विपक्षी पार्टियों के शीर्ष नेता, एकता बैठक में शिरकत कर रहे हैं। ये सभी नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को टक्कर देने की पुख्ता रणनीति तैयार करेंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर किसी फॉर्मूले पर सहमति बन सकती है। इससे पहले पटना में हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में करीब डेढ़ दर्जन पार्टियों के नेता ही पहुंचे थे। हालांकि दूसरी बैठक के लिए तिथि और स्थल, दोनों में बदलाव किया गया। पहले यह बैठक, 13 और 14 जुलाई को शिमला में होनी थी, लेकिन बाद में इसे बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया गया। तिथि भी 17 और 18 जुलाई हो गई। पहली बैठक के बाद एक समय ऐसा भी आया, जब विपक्षी कुनबा बिखराव की राह पर आ पहुंचा। वजह, अरविंद

■ आप की शर्त मानने की इनसाइड स्टोरी

केजरीवाल इस जिद पर अड़े रहे कि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ आप का साथ देना होगा। इस मुद्दे पर आप ने पटना की बैठक में अपने तेवर दिखा दिए थे। एकता की इनसाइड स्टोरी में एक समय वह भी आया, जब विपक्षी कुनबा टूटते-टूटते बचा। कांग्रेस पार्टी ने अपने नेताओं की नाराजगी मोल लेकर विपक्षी कुनबे में केजरीवाल का साथ देने की घोषणा कर दी।

23 जून को पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक हुई थी। उससे पहले आम आदमी पार्टी के भीतर से ऐसी आवाजें सुनाई पड़ी कि पटना की बैठक में कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों ने अगर दिल्ली सरकार के लिए लाए गए केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा नहीं की तो आप बैठक से किनारा कर सकती है। विपक्षी दलों को इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, दोनों ने बैठक में शिरकत की। ये बात अलग रही कि जब विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रेसवार्ता की, तो उसमें आप नेता शामिल नहीं हुए। बैठक खत्म होने के बाद ही केजरीवाल और मान, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद कांग्रेस और आप के नेताओं के कई ऐसे बयान सामने आए, जिससे विपक्षी एकता मुश्किल में पड़ती हुई दिखाई दी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने धैर्य से काम लिया। राहुल गांधी ने पटना की बैठक से पहले कहा, हम सब मिलकर मोदी से लड़ेंगे। कांग्रेस का मतलब देश के गरीबों के साथ खड़े होना और उनके लिए काम करना है। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, अध्यादेश का विरोध तो सदन में होता है। अभी से इसका प्रचार क्यों हो रहा है। विपक्ष को मिलकर, भाजपा के खिलाफ लड़ना है।

प्रमुख समाचार

चिराग पासवान अमित शाह से मिले, राजग में शामिल

नईदिल्ली। एक ओर जहां 2024 चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की बड़ी बैठक बेंगलुरु में होनी है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी अपने कुनबे को लगातार मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में आज लोक

जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता और बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे चिराग पासवान की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। इसके बाद वह भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान सोमवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में शामिल हो गए। 18 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। पासवान 2024 के आम चुनावों के लिए बिहार में लोकसभा सीट के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भाजपा के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। शाह से उनकी मुलाकात को इसी कवायद के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इससे पहले चिराग से दो बार मुलाकात कर चुके हैं। चिराग के पिता और दिवंगत दलित नेता रामविलास पासवान के नेतृत्व में अविभाजित लोजपा ने 2019 में बिहार की छह लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ा था। और

अध्यादेश को लेकर केंद्र ने दिल्ली सरकार पर लगाए आरोप

नईदिल्ली। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अध्यादेश को तत्काल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी को पंगु बनाने और सतर्कता विभाग के अधिकारियों को परेशान करने का प्रयास कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक नोटिस जारी किया, जहां उसने कहा कि वह इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को सौंपने के इच्छुक है। वहीं, केंद्र ने दिल्ली अध्यादेश का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दायर किया। गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अध्यादेश को तत्काल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली सरकार राजधानी को पंगु बनाने और सतर्कता विभाग के अधिकारियों को परेशान करने का प्रयास कर रही थी। सतर्कता विभाग की फाइलों में उत्पाद शुल्क नीति मामले की फाइलें, अरविंद केजरीवाल के नए बंगले से संबंधित फाइलें भी शामिल थीं। दिल्ली सरकार के विज्ञापनों की जांच और दिल्ली की बिजली सब्सिडी आदि सभी को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने सतर्कता विभाग से गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया।

अमेरिका में 80 हजार भारतीयों ने खरीदी बंदूकें

नईदिल्ली। अमेरिका का संविधान अपने हर नागरिक को बंदूक रखने का अधिकार देता है। जितनी आसानी से फल और सब्जियां मिलती हैं आप दुकान पर चाहिए और अपनी मनपसंद गन

खरीद सकते हैं। इसका नतीजा यह है कि पिछले 50 सालों में अमेरिका में 15 लाख से यादा लोग बंदूक के जरिए होने वाली हिंसा में मारे गए। अमेरिका में बंदूक की संस्कृति उस जमाने से है जब वहां पर ब्रिटिश शासन था। तब आकर पुलिस कोई स्थाई सुरक्षा बल नहीं था। लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती थी। लोगों को कहा गया कि आप अपने हथियार खरीद लीजिए और अपने और अपने परिवार की रक्षा स्वयं कीजिए। अमेरिका में तो स्कूल के छोटे-छोटे बचों के पास भी बंदूके हैं। आपने स्कूलों में शूटआउट की कई खबरें सुनी होंगी। अब इतने लोगों के हाथों में बंदूके होंगी तो हिंसा को कोई नहीं रोक सकता। पिछले 50 सालों में अमेरिका के बदनाम गन कल्चर के चलते 15 लाख लोगों की जान गई है। यादातर हमले कालों और गोरों के बीच हुई है।

बंगाल में लेफ्ट-टीएमसी का नहीं होगा गठबंधन : येचुरी

नईदिल्ली। सीपीआई (एम) के महासचिव ने कहा कि हर राय में स्थिति अलग है। कोशिश ये है कि इन स्थितियों में बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले वोटों का बंटवारा कम से कम हो। यह कोई

नई बात नहीं है। जैसे 2004 में लेफ्ट के पास 61 सीटें थीं, जिनमें से हमने कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर 57 सीटें जीतीं। बेंगलुरु में दूसरी विपक्षी एकता बैठक की पूर्व संध्या पर एक बड़ी घोषणा में, सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया। आश्चर्य की बात जो यह है कि कर्नाटक में ये दोनों दल विपक्ष की बैठक में भागीदार है। लेकिन बंगाल में एक साथ आने को तैयार नहीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम राय में भाजपा और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। गौरतलब है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की रणनीति बनाने की कोशिश में 26 विपक्षी दल कल सुबह 11 बजे बेंगलुरु में बैठक करेंगे।

कश्मीर विश्वविद्यालय प्रवक्ता समेत 3 अफसरों की सेवा समाप्त

नईदिल्ली। अभिनय आकाशनवीनतम कदम सरकार द्वारा उसी कानून के तहत शोपियां बलात्कार-हत्या विवाद में कथित रूप से शामिल दो डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने के एक महीने से भी कम समय बाद आया है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने राय की सुरक्षा के लिए खतरा होने के कारण तीन और सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। उन्हें संविधान के अनुछेद 311(2)(सी) के तहत समाप्त कर दिया गया है जो सरकार को किसी कर्मचारी को बिना जांच किए बर्खास्त करने की अनुमति देता है। नवीनतम कदम सरकार द्वारा उसी कानून के तहत शोपियां बलात्कार-हत्या विवाद में कथित रूप से शामिल दो डॉक्टरों की सेवाओं को समाप्त करने के एक महीने से भी कम समय बाद आया है।आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) फहीम असलम, राजस्व अधिकारी मुरावत हुसैन मीर और पुलिस अधिकारी अरशद अहमद थोकर को बर्खास्त करने का आदेश सोमवार को दिया गया। फहीम असलम, जिनके पास कश्मीर विश्वविद्यालय से जनसंचार और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है, 2008 से विश्वविद्यालय में पीआरओ हैं। इससे पहले, उन्होंने स्थानीय अंग्रेजी दैनिक ग्रेटर कश्मीर के लिए एक संवाददाता के रूप में काम किया था।

विश्लेषण

आर्थिक विकास को बढ़ावा और बड़े स्तर पर रोजगार देगा संशोधित बीमा विधेयक

मधुरेंद्र सिन्हा

अब जबकि संसद का मानसून सत्र आ चला है, कई विधेयकों पर सभी की नजर है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो आर्थिक, वित्तीय और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनमें एक ऐसा विधेयक है, जिसे सुधारवादी ही नहीं, रोजगार प्रेरक माना जा रहा है। यह बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 है और पारित होने पर यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके पारित होने पर बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते खुलेंगे और निवेश भी बढ़ेगा। इसे इसी सत्र में रखा जाएगा और लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होने के कारण इसका पारित होना तय ही है। उम्मीद है कि इसे राज्यसभा में भी पारित होने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी।

यह विधेयक 1938 में बने बीमा कानून में संशोधन तो करेगा ही, 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कानून में भी बदलाव लाएगा। इस संशोधन के बाद यह कानून बड़े उद्यमों तथा बीमा कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा। सरकार का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी तादाद में नई कंपनियां उतरेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा।

विकसित देशों की तुलना में भारत में बहुत कम लोग व्यक्तिगत बीमा के अंदर आते हैं। लेकिन सरकार के प्रयासों और आर्थिक मदद की वजह से 2021 तक 51 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य बीमा हो चुका था। और इस मद में बीमा उद्योग की सकल प्रीमियम आय 470 अरब रुपये थी। भारत वैश्विक स्तर पर

दुनिया का नवां बीमा प्रीमियम बाजार है, लेकिन देश की आबादी का महज 3.30 फीसदी ही जीवन बीमा के दायरे में है। इसे ध्यान में रखकर बीमा नियामक आईआरडीएआई ने 2047 तक %सभी के लिए बीमा% का मिशन शुरू किया है, जिससे बीमा पैठ में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी तथा क्षेत्र को अधिक निवेश-अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी। इससे 2027 तक ही भारतीय बीमा बाजार के 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी भारत में महज 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं और 31 सामान्य बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद सामान्य कंपनियां भी बीमा के कारोबार में कदम रख सकती हैं।

यह विधेयक इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें बीमा कंपनी खोलने के लिए बाध्यकारी 100 करोड़ रुपये की सीमा को खत्म किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक कारोबारी इस क्षेत्र में कदम रख सकें। अब भारत में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा एक साथ हो सकेंगे, जिससे बीमाधारक को बड़ी-बड़ी हेल्थ कंपनियों की सेवाएं बीमा के पैसे से ही मिल सकेंगी। अमेरिका-यूरोप में ऐसी व्यवस्था पहले से है। भारत में सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का काम शुरू कर चुकी है। इससे इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा।

संसद के मानसून सत्र में इस बार कई और भी विधेयक रखे जाएंगे, जिनमें कंपनियों के दिवालिया होने पर आगे उनके अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए भी एक विधेयक है, जिससे समय बर्बाद नहीं होगा और पुरानी कंपनी को कोई नई कंपनी अपने हाथ में ले सकेगी। दरअसल, यह 2016 में बनाए गए इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन है, जिससे दीवालियापन की प्रक्रिया में तेजी आए और सबसे उपयुक्त दावेदार को शीघ्र उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि संपत्ति बर्बाद न हो। इस बार कर कानूनों में संशोधन से भी जुड़ा विधेयक रखा जाएगा, जिससे टैक्स देने वालों को आसानी होगी और जटिलता खत्म होगी। लेकिन संसद के पिछले सत्र में हमने देखा कि विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि दोनों सदनों के कामकाज में बहुत बाधा पहुंची और कई सारे बिल धरे रह गए। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वह संसद में हंगामे के लिए तैयार है। इसके लिए वह मणिपुर में हुई हिंसा को मुद्दा बनाएगी। इसके अलावा, चूंकि सत्तारूढ़ दल ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) से जुड़े विधेयक को लाने का इरादा जताया है, उस पर भी हंगामा हो सकता है। जाहिर है, इसमें संसद का काफी समय बर्बाद होगा और कई महत्वपूर्ण विधेयक प्रभावित हो सकते हैं।

अबूझमाड़ के बच्चे मलखंब में नारायणपुर का नाम रोशन कर रहे हैं: कश्यप

■ छत्तीसगढिया ओलंपिक का किया शुभारंभ

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के अवसर पर छत्तीसगढिया ओलंपिक का आयोजन जिले के ग्राम पंचायत गरांजी में विधायक एवं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप के द्वारा शुभारंभ किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा छत्तीसगढ़ में तीज त्यौहार परंपराओं को सवारने एवं सहजने का कार्य शुरुआत किया गया है, उसे सहेज कर रखने की आवश्यकता हम सभी का होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, रहन सहन, वेशभूषा सहित परंपरा और संस्कृति को सवारने का जो कार्य किया जा रहा है, वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा की छत्तीसगढिया ओलंपिक के माध्यम से 16 प्रकार के खेल विधाओं का शुभारंभ किया गया है, जिससे लोगों में एक दूसरे का पहचान बढ़ेगा। यह ओलंपिक सबसे पहले गांव से प्रारंभ होकर जिला स्तर से संभाग फिर राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप लोग बढ़-चढ़कर भाग ले सकते हैं।

श्री कश्यप ने कहा कि ग्रामीणजन सभी खेलों से परिचित होते हैं और जितने की मुझे पूरा विश्वास है। उन्होने राज्य स्तर पर पहुंचने के लिए जिले के खिलाडियों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं दी।। उन्होंने कहा कि जिले के अबूझमाड़ अब अबूझ नहीं रहा है, जिला प्रशासन द्वारा अबूझमाड़

का विकास करने के लिए शासकीय योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अबूझमाड़ के बच्चे मलखंब में देश और दुनिया में नारायणपुर का पहचान बना चुके हैं, इसके लिए मैं उन खिलाडियों को बधाई देता हूं। ऐसी ही छत्तीसगढिया ओलंपिक में भी अच्छे प्रदर्शन कर राज्य स्तर में भी नारायणपुर जिले का नाम रोशन करने की शुभकामनाएं दी।

श्री चंदन कश्यप ने कहा कि हरेली त्यौहार के शुरुआत से किसानों में अच्छी फसल की पैदावार की कामना करते हुए इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन किसानो नें कृषि यंत्र का पूजा अर्चना कर फसल की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, सांसद प्रतिनिधि अजय देशमुख, जय वट्टी, कलेक्टर अजीत वसंत और पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा ने भी संबोधित किया। हरेली तिहार के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के द्वारा नारियल फेंक प्रतियोगिता आयोजित किया गया तथा छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुभारंभ महिलाओं के द्वारा रस्साकसी से शुभारंभ किया गया, जिसमें ठेकापारा गरांजी के महिलाओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रस्साकसी में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले महिलाओं को विधायक द्वारा पुरस्कार भी दिया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक विधा का 100 मीटर दौड़ का विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरूआत किया गया। कार्यक्रम के उपरांत श्री चंदन कश्यप द्वारा एजुकेशन हब गरांजी के मैदान में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, कलेक्टर श्री वसंत, पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, जिला पंचायत सीईओ देवेश कुमार द्वारा पौधे का रोपण किया। इस अवसर पर नगरपालिका उपाध्यक्ष प्रमोद नेलवाल, सरपंच गरांजी पिलसाय सलाम, रघु मानिकपुरी, जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

विधायक कश्यप ने कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का किया अनावरण

नारायणपुर। छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली के उपलक्ष्य में विधायक एवं छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप ने आज नारायणपरु कलेक्ट्रेट परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया और पुष्पार्पित कर उन्हें नमन किया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सभी जिलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके। विधायक ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है और बोरे-बासी को आज पूरा देश जानने लगा है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, सांसद प्रतिनिधि अजय देशमुख, जय वट्टी, बोधन देवांगन, रघु मानिकपुरी, कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा, जिला पंचायत सीईओ देवेश कुमार ध्रुव, जनपद सीईओ घनश्याम जांगड़े सहित जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे।

संसदीय सचिव बंजारे ने छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक खेल का किया शुभारंभ

■ बिल्लुस, फुगड़ी, गेड़ी, दौड, भंवरा सहित 16 पारम्परिक खेल

बेमेतरा। छत्तीसगढिया ओलम्पिक जिला स्तरीय खेल का शुभारंभ रिमझिम फुहारों के बीच आज जवाहर लाल नेहरु कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में संसदीय सचिव व विधायक नवागढ़ श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा-अर्चना की।

इस मौके पर अतिथियों द्वारा परिसर में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इस अवसर पर सीईओ ज़िला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मण्डावी, अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार वाजपेयी, छन्नुलाल मार्कण्डेय, एसडीएम सुश्री सुरुचि सिंह, डिप्टी कलक्टर, नगरपालिका अधिकारी सहित अन्य ज़िला अधिकारी,स्कूल, कॉलेज के छात्र-छात्रा सहित गणमान्य नागरिक व खेल प्रेमी उपस्थित थे। संसदीय सचिव श्री गुरुदयाल सिंह बंजारे कहा कि हमारी लोककला और संस्कृति विलुप्त हो रही थी । वही पारंपरिक खेल भी आधुनिकता की दौड़ में पीछे छूट रहे। इस को मुख्यमंत्री ने महसूस किया और पारंपरिक छत्तीसगढिया ओलम्पिक पिछले साल खेल का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती ।लक्ष्य बनाकर इसे पूरा करें ।तभी आप लक्ष्य हासिल कर सकते है।

संसदीय सचिव ने कहा कि से आज से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ बेमेतरा ज़िले में भी हरेली तिहार का आयोजन हो

रहा साथ ही छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेलो का अगाज हो गया है। उन्होंने सभी को हरेली तिहार और छत्तीसगढिया ओलम्पिक की बधाई और शुभकामनाएँ दी। उन्होंने नारियल फेंक और महिला रस्सा कस्सी का का आनंद लिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत व कार्यक्रम की नोडल अधिकारी श्रीमती लीना मण्डावी ने स्वागत भाषण में कहा कि आधुनिक परिवेश में काल के ग्रास बनते जा रहे छत्तीसगढ़ के पारम्परिक खेलों से नयी पीढ़ी को अवगत कराने के लिए छत्तीसगढिया ओलम्पिक का शुभारम्भ सरकार द्वारा की गई। छत्तीसगढ़ में दूसरी बार हो रही पारम्परिक खेलों और खेल.कूद प्रतियोगिता का बेमेतरा ज़िले में जबरदस्त उत्साह है। खेल जिला, संभाग,और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता होंगी। इस बार दो नये खेल जुड़े हैं । अभी राजीव मितान क्लब के माध्यम खेल खेला गया ।

कृषि आदान विक्रय केंद्रों पर निरीक्षण दल की छापेमारी

अनियमितता पर तीन प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी

भाटापारा। अनुविभागीय कृषि अधिकारी, बलौदा बाजार जय इंद्र कंवर के अगुवाई में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा भाटापारा के कीटनाशक, उर्वरक एवं बीज विक्रय केंद्रों में छापेमारी की गई। इस दौरान विक्रय केंद्रों के समस्त दस्तावेज खंगाले गए। तीन प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब मांगा गया है।

भाटापारा के विनय इंटरप्राइजेस के निरीक्षण में विक्रय केंद्र में स्त्रोत प्रमाण पत्र, स्कंध पंजी, उपलब्ध स्कंध तथा मूल्य सूची नहीं पाया गया। कृषकों को दिए जा रहे बिल में कीटनाशक के बैच नंबर का उल्लेख नहीं था। इसी प्रकार लखन जानकी पेस्टीसाइड, हटरी बाजार, भाटापारा में भी निरीक्षण के दौरान स्कंध पंजी तथा निर्धारित प्रारूप में बिल बुक नहीं पाया गया। कृषकों को दिए जा रहे बिल में कीटनाशक के बैच नंबर का उल्लेख नहीं था और कृषकों के हस्ताक्षर भी नहीं थे। भाटापारा के ही कृषि सोपान में कृषकों को निर्धारित प्रारूप में बिल नहीं दिए जा रहे थे, जो कीटनाशी नियम, 1971 के नियमों का स्पष्ट उलंघन है। कीटनाशक विक्रय केंद्रों में पाए गए अनियमितताओं के कारण कार्रवाई करते हुए तीन प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सामाधान कारक जवाब नही मिलने पर कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियम, 1971 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

एनसीएसटी ने कलेक्टर से पूछा- राजस्व ग्राम की सुविधा के लिए क्या किया?

■ नगरी-मगरलोड के 110 गांवों को राहत

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नगरी और मगरलोड ब्लॉक के 110 गांवों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं को लेकर राहत की खबर है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर पूछा है कि 110 ग्रामों को राजस्व ग्रामों जैसी सुविधाएं देने की दिशा में क्या कार्रवाई हुई है? इसकी जानकारी तत्काल उपलब्ध करवाई जाए। आयोग ने यह भी कहा है कि कलेक्टर के जवाब नहीं देने पर उनके विरुद्ध अनुच्छेद 338 (क) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह नोटिस भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम के शिकायत पत्र पर संज्ञान लेते हुए दिया है।

दरअसल, राजस्व ग्राम की सुविधा को लेकर ग्रामवासी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने भी इन्हें समर्थन दिया है। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। जिसके बाद आयोग ने नोटिस जारी किया है। मरकाम ने इससे पहले स्थानीय विधायक को जनविरोधी बताते हुए

उन्हें 110 ग्रामों के प्रति संवेदनहीन बताया था। मरकाम ने कहा कि उम्मीद है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संज्ञान लेने के बाद राज्य सरकार शीघ्र ही राजस्व ग्राम जैसी सुविधाएं देगी।

उन्होंने कहा कि, नगरी मगरलोड ब्लाक के 110 ग्रामों की सुविधाओं के लिए चल रहे आंदोलन प्रयास और संघर्ष को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पत्र पर संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर को कार्यवाही का लिखित जवाब दाखिल करने के लिए आदेशित किया है। 110 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों की भांति सुविधाएं मिले इस दिशा में निश्चित ही यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा और ग्रामीणों को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

मुआवजा व मांगों को लेकर कंवर के नेतृत्व में चक्काजाम

कोरबा। राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित निजी जमीन को शासकीय बता मुआवजा नहीं देने समेत नौ सूत्रीय मांग को लेकर विधायक ननकीराम कंवर की अगुवाई में चक्काजाम कर दिया गया। इससे कोरबा-चांपा मार्ग में वाहनों के पहिए थम गए और वाहन कतारबद्ध होकर खड़े हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बरपाली के मेनरोड़ में रविवार की शाम तीन बजे से पूर्व गृहमंत्री व विधायक कंवर के साथ भाजपा व कार्यकर्ता टैंट लगा कर बैठ गए। इससे मार्ग में गुजर रहे चालकों को अपना वाहन रोकना पड़ गया। इस दौरान वक्ताओं ने अपनी नौ सूत्रीय मांग बताते हुए कहा कि कोरबा-चांपा फोर लेन सड़क निर्माण के लिए प्रभावितों के निजी जमीन को शासकीय भूमि बताकर उचित मुआवजा नही दिया जा रहा है। इसी तरह उरगा-पत्थलगांव भारत माला के लिए निर्धारित किसानों को मुआवजा की विसंगति दूर नहीं की गई है। उरगा स्थित खनिज विभाग जांच नाका को कीचड़ एवं धूल प्रदुषण से मुक्त किया जाना चाहिए।

तीन बहनों की डूबने से मौत गांव वालों ने किया चक्काजाम

बिलासपुर। ग्राम सेंदरी में तीन बहनों की अरपा नदी में डूबने से मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई लेकिन गांव वालों ने नदी में अवैध उत्खनन के कारण हादसे का आरोप लगाकर चक्का जाम कर दिया है। जिसके कारण बिलासपुर-अंबिकापुर हाईवे में दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाइश दे रहे हैं। कोनी थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा ने बताया कि सोमवार की सुबह सेंदरी में रहने वाली पूजा पटेल, रितु पटेल और धनेश्वरी पटेल नदी में नहाने के लिए गई थी। इस दौरान धनेश्वरी नदी के बहाव में डूबने लगी। इसे देख रितु और पूजा ने उसे बचाने का प्रयास किया। नदी में बहाव तेज होने के कारण रितु और पूजा भी पानी में बह गए। आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी गांव वालों को दी, साथ ही तीनों बहनों की खोज शुरू की गई। गांव वालों ने तीनों बहनों के शव को पानी से निकाल लिया है। घटना की सूचना पर कोनी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।

स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में शामिल हुईं विधायक

धमतरी। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर ओरियन एजुकेशन सोसायटी धमतरी द्वारा स्किल डे किट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रंजना डीपेंद्र साहू शामिल हुईं जहाँ प्रशिक्षित युवाओं से उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा चल रही स्किल इंडिया,प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। विधायक रंजना साहू ने मां सरस्वती की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण ले रहे हैं प्रशिक्षार्थीयों ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से सिखाए जा रहे हैं विभिन्न कौशल प्रशिक्षण को विधायक के समक्ष दिखाया जिस पर विधायक ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के युवाओं को कौशल से परिपूर्ण हुनरमंद और कुशल श्रम शक्ति बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नई पीढ़ी का कौशल विकास एक राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत की नींव है।

हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के आत्मा में बस्ती हैं : सोनी

कोरबा। बालको के नवयुवकों द्वारा पिछले वर्ष की भांति आयोजित सार्वजनिक हरेली उत्सव में शामिल हुवे राजीव युवा मितान क्लब के जिला संयोजक श्यामनारायण सोनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बालको के उर्जावान युवाओं को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हुं। युवाओं ने अपने प्रयास से छतीसगढ़ीहा संस्कृति को जतन करके हरेली त्यौहार का सफल आयोजन किया। हरेली त्यौहार हम छत्तीसगढ़ियों का प्रथम त्यौहार हैं यह हमारे अन्नदाताओं के सम्मान में छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित किया जाता है। किसान हल और अपने खेती के औजारों की पूजा करते हैं, हमे अपनी छतीसगढ़ीहा संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार छत्तीसगढ़ की आत्मा हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को संवारने और आमजन को संस्कृति पर गर्व करना सिखाया हैं, आज पूरे छत्तीसगढ़ नही पूरे देश एवम विश्व मे छत्तीसगढ़ संस्कृति को विशेष पहचान मिली है, 17 जुलाई से छत्तीसगढ़ीया ओलंपिक की सुरुवात हुई। हम सभी को इस महा ओलंपिक में भाग लेकर अपनी संस्कृति का आनंद लेना चाहिए।

इस भैरी सरकार से अपनी सड़क लेकर रहेंगे : रंजना

धमतरी। कोलियारी खरेंगा दोनर मार्ग की बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण की मांग लगातार तेज़ हो रही है बीते दिनों उसी जर्जर मार्ग पर सड़क हादसे में एक शिक्षक के हाईवा के चपेट में आने से मौत हो गई,उसी दिन भाजपा द्वारा चक्काजाम किया गया था उसके पश्चात सड़क संघर्ष समिति के द्वारा आज अपनी सड़क की मांग को लेकर रायपुर राजधानी कूच किया गया जिसका विधायक रंजना डिपेंद्र साहू ने चंदन माला श्रीफ्ल देकर ग्रामीणों का सम्मान किया और अपने हक की लड़ाई में जागरूक जनता को स्वयं आगे आने साधुवाद दिया। रविवार सुबह कोलियारी से निकली इस पदयात्रा की शुरुआत में पहुंची विधायक ने कहा पिछले साढ़े चार वर्षों से हम इस सड़क की मांग कर रहे हैं ना जाने इस सरकार को हमारे क्षेत्र से क्या भेदभाव है कि इतने सड़क हादसों के बावजूद इस सड़क की स्वीकृति नहीं दे रही है,हमने इसकी मांग सदन पर भी उठाई विभागीय मंत्रियों से मिलकर मांग की पदयात्रा निकाली उसके बाद इस भैरी सरकार को जनता की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही।

जमीन फर्जीवाड़े को लेकर वर्तमान और पूर्व विधायक आमने सामने

मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी। जमीन फर्जीवाड़े को लेकर एमसीबी जिले में वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक आमने सामने हैं। पूरा मामला मनेंद्रगढ़ में 22 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का है। मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल ने रविवार को प्रेस वार्ता पर भाजपा के नेताओं और अधीकारियों द्वारा जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री किये जाने के आरोप लगाया है।

यह लगभग 22 एकड़ 87 डिसमिल की जमीन खरीदी बिक्री का मामला है। यह केस अलग अलग कमिश्नर से लेकर राजस्व मंडल और हाईकोर्ट में चला। सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी थी। विधायक विनय जायसवाल का आरोप है कि राहुल सिंह और अन्य भाजपा नेता फर्जी तरीके से 22 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराए है। इस फर्जीवाड़े में जो भी अधिकारी संलिप्त है, उन पर भी

एफआईआर होगी। इसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारियों से की है। साथ ही राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री से भी शिकायत करने की बात विनय जायसवाल कर रहे हैं।

जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोप

मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल का आरोप है कि, भाजपा नेताओं और अधीकारियों के मिलीभगत से फर्जी तरीके से इस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। जमीन का एक समय पर कब्जा पट्टा होता है। जिसके बाद जिनका जमीन था, उसको दिये गए कर्ज के वसूली के लिए बंधक बनाया गया और जबरदस्ती जमीन की रजिस्ट्री कराई।

जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप

इस संबंध में जब भाजपा के पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल से पूछा गया, तो श्याम बिहारी का कहना है कि, मेरे पास तो 2002 से दो-दो राइस मिल हैं। मेरे पिताजी किसानी का काम करते थे, मैं भी किसान था और जमीन जायदाद पुरखों से हमारे पास है। विधायक कार्यकाल में मैंने 10 एकड़ जमीन खरीदा था। जिसमें से 5 एकड़ मैंने बेच भी दिया था। उनको जो भी जांच कराना है, करा सकते हैं। अब तक क्या कर रहे हैं, कुछ करना था इनको, क्यों जांच और कार्रवाई नहीं किया। यह सिर्फ फिजूल की बातें कर रहे हैं। आम जनता को गुमराह करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है।

इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की है और डॉक्टर विनय जायसवाल मनेंद्रगढ़ से कांग्रेसी विधायक हैं। फिर भी जमीन फर्जीवाड़ा को लेकर अभी तक पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं कराया गया। मामले के लेकर ना ही किसी प्रकार की जांच हो पाई है। क्या यह माना जाये कि चुनावी मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है।

कांकेर के करकापाल कैंप में सीएएफ जवान ने की 30 राउंड फायरिंग, जांच में जुटी पुलिस

कांकेर। दुर्गूकोंदल थाना क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रविवार देररात करकापाल कैंप में सीएएफ (छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स) जवान ने तकरीबन 30 राउंड फायरिंग की। कांकेर एसपी दिव्यांग पटेल ने फायरिंग की पुष्टि तो की, लेकिन यह फायरिंग क्यों की गई, इसका खुलासा फिलहाल अभी नहीं किया गया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

करकापाल कैंप में सीएएफ जवान ने क्यों और किन हालातों में फायरिंग की, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसिक तनाव में आकर जवान ने 30 राउंड हवाई फायरिंग की है। फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही रविवार देर रात की घटना का खुलासा हो पाएगा।

जानिए कांकेर में कब कब जवान ने की फायरिंग

25 दिसम्बर 2022- कांकेर के शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय का अधिग्रहण स्ट्रांग रूम के लिए किया गया था। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में ड्यूटी पर तैनात 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान ने आपसी विवाद में फायरिंग कर दी। इसमें प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र भगत की मौत हो गई।

28 अप्रैल 2022- इस दिन बीएसएफ के एक जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। जवान पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। घटना कांकेर के कामटेडा कैंप की थी। मृतक उज्जवल नंदी बीएसएफ की 30वीं बटालियन का जवान था।

नक्सलियों से लोहा लेने वाले जवान कई बार मानसिक तवान के चलते आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। 2009 के बाद फिर से मामले बढ़ने लगे थे और वर्ष 2012 में सबसे अधिक पांच जवानों ने आत्महत्या की। इसके बाद फिर ऐसे मामलों में काफी कमी आई। अब फिर से ऐसी घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

निर्विरोध राज्यसभा पहुंचेंगे एस जयशंकर समेत 11 प्रत्याशी

नईदिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन उन 11 नेताओं में शामिल हैं जिनका राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुना जाना तय है। कथित तौर पर, छह तृणमूल कांग्रेस और पांच भाजपा उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। सत्तारूढ़ भाजपा को एक सीट का फायदा हुआ है और राज्यसभा में उसके 93 सदस्य हैं, जहां सरकार के पास बहुमत नहीं है। चुनाव आयोग ने गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी - जो 24 जुलाई को होंगे। आयोग ने कहा कि गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल के 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण राज्यसभा में जो सीटें खाली होनी हैं उनमें पश्चिम बंगाल से डेरेक ओ ब्रायन और गुजरात से एस जयशंकर शामिल हैं।

लगातार दूसरे दिन शरद पवार से मिले अजित गुट के नेता

मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के बागी विधायकों ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन मुंबई के वाईबी चव्हाण सेंटर में पार्टी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। बैठक के बाद एनसीपी के बागी नेता और राज्यसभा सदस्य प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पार्टी विधायक शरद पवार का आशीर्वाद लेने आए हैं। वरिष्ठ पवार से मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि आज अजित पवार, सुनील तटकरे और मैंने वाईबी चव्हाण केंद्र में शरद पवार से मुलाकात की। हमने उनसे फिर से एनसीपी को एकजुट रखने का अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात सुनी लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा। रविवार को अजित पवार ने प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटिल के साथ वाईबी चव्हाण सेंटर में एनसीपी सुप्रीमो से मुलाकात की थी। बैठक के बाद अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि हम सभी आज आदरणीय शरद पवार का आशीर्वाद लेने के लिए यहां आए थे। हमने पवार साहब से अनुरोध किया कि एनसीपी को एकजुट रहना चाहिए।

केजरीवाल ने समर्थन के लिए खड़गे का आभार जताया

नयी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी (आप) का समर्थन करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का सोमवार को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर जी जान से लड़ना चाहिए। केजरीवाल का यह बयान तब आया है जब आज बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की दो दिवसीय अहम बैठक होने वाली है जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता से बाहर करने की संयुक्त रणनीति का एजेंडा तय किया जाएगा। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''दिल्ली के लोगों का साथ देने के लिए शुक्रिया खरगे जी। यह अध्यादेश भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी है तथा इससे जी जान से लड़ना होगा।'' भाजपा नीत केंद्र सरकार मई में दिल्ली में नौकरशाहों के तबादले और तैनाती पर अध्यादेश लेकर आयी थी, जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का प्रभाव खत्म हो गया था, जिसमें सेवाओं पर नियंत्रण निर्वाचित सरकार को दिया गया था।

सपा को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक पद से इस्तीफा देने के दो दिन बाद दारा सिंह चौहान सोमवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। वह दोपहर करीब 12 बजे उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुए। सपा विधायक पद से इस्तीफा देने से एक दिन पहले चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। 2022 में सपा में शामिल होने से पहले, वह भाजपा का हिस्सा थे और 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि दारा सिंह चौहान बड़े ओबीसी नेता हैं। वह कहीं नहीं गए (चौहान 2017 से 2022 के बीच यूपी के कैबिनेट मंत्री थे)। वह पार्टी के सदस्य हैं और हम उनका सम्मान करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एलजी और केजरीवाल को दी नसीहत

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना को राजनीतिक कलह से ऊपर उठकर राष्ट्रीय राजधानी में शासन के गंभीर काम में उतरने की जरूरत है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वी के सक्सेना से बैठक करने और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों पर विचार करने को कहा। न्यायालय ने दिल्ली सरकार की याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करना तय किया। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के नामित अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने ऐसी नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले केंद्र के हालिया अध्यादेश के एक प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने का निर्णय लेते हुए यह फैसला सुनाया।

कांग्रेस का भाजपा पर तंज

प्रधानमंत्री मोदी को अचानक एनडीए याद आया

नई दिल्ली। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी एकता देश के राजनीतिक परिदृश्य के लिए गेम चेंजर साबित होगी। कांग्रेस ने इसके साथ ही सत्ताधारी भाजपा पर भी तंज कसा और कहा कि जो लोग अकेले विपक्षी पार्टियों को हराने की बात करते थे, वह अब भूत बन चुके एनडीए में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि यह पटना में हुई विपक्षी बैठक का नतीजा है।

विपक्षी एकता की दो दिवसीय बैठक बेंगलुरु में सोमवार से शुरू हुई। उससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा कि एनडीए में नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। पहले एनडीए के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी लेकिन अब अचानक से बीते कुछ दिनों से हम इसके बारे में पढ़ और सुन रहे हैं। अचानक से एनडीए की मंगलवार को बैठक बुलाई गई है। तो एनडीए, जो भूत बन चुका था, अब उसमें फिर से नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है।

जयराम रमेश ने कहा कि यह पटना में हुई विपक्षी बैठक का नतीजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि लोग वक्त आने पर उन लोगों को सबक सिखाएंगे, जो प्रशासन में बुरी तरह विफल हुए हैं और जिन्होंने लोगों के साथ झूठे वादे कर धोखा किया। वेणुगोपाल ने कहा कि 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर लोगों की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए आगे बढ़ रही हैं।

बेंगलुरु में होने वाली बैठक को लेकर वेणुगोपाल ने कहा कि यह दूसरी बैठक है। इस बैठक में भविष्य की योजना बनाई जाएगी। 20 जुलाई से संसद का सत्र भी शुरू होगा। इसके लिए भी विपक्षी बैठक में योजना बनाई जाएगी। बता दें कि बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक में कई और राजनीतिक पार्टियां भी जुड़ सकती हैं।

विपक्ष की बैठक से पीएम और बीजेपी परेशान

बेंगलुरु में दूसरी विपक्षी बैठक से पहले, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोमवार (17 जुलाई) को अन्य दलों के प्रमुख नेताओं को शामिल करने के प्रयास को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया और कहा कि भगवा पार्टी एनडीए में नई जान फूंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह जो कि 23 जून को पटना में कई पार्टियों के

जमावड़े का नतीजा है। जयराम ने आरोप लगाया कि विपक्ष के एक ही मंच पर जुटने से बीजेपी परेशान है और इसलिए उसने 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है।

कर्नाटक की राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया कि कुछ वरिष्ठ नेता सोमवार को बैठक में भाग नहीं ले रहे हैं, लेकिन मंगलवार को इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ नेता सोमवार को नहीं आ रहे हैं मंगलवार को आएंगे और यह बैठक मंगलवार को सुबह होने वाली है। 11 बजे बैठक शुरू होगी और शाम 4 बजे सभी पार्टियों के नेता देश को संबोधित करेंगे।

कुमारस्वामी का विपक्षी एकता में शामिल होने से इनकार

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और जद (एस) नेता एचडी कुमारस्वामी, जो पटना में पहली संयुक्त विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, अब एनडीए के साथ हाथ मिलाने पर विचार कर रहे हैं और औपचारिक निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। इस बाद की जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में एनडीए सहयोगियों की बैठक बुलाई है। हालांकि, सूत्रों ने कहा कि जद (एस) नेता ने भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने के लिए एक शर्त रखी है। सूत्रों ने कहा, कुमारस्वामी ने एनडीए में शामिल होने के बदले अपनी पार्टी को विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है।

भाजपा खेमे से निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर जद (एस) के कुमारस्वामी ने कहा, एनडीए ने हमारी पार्टी को किसी भी बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया है। हम उस मोर्चे पर देखेंगे। उन्होंने संयुक्त विपक्ष की भी आलोचना की, जो अगले साल भाजपा से मुकाबला करने की रणनीति बनाने के लिए आज से बेंगलुरु में दो दिनों की बैठक कर रहा है और कहा कि उन्होंने कभी भी उनकी पार्टी को अपना हिस्सा नहीं माना।

विपक्षी पार्टियों की बैठक पर उपेन्द्र कुशवाहा ने कसा तंज

पटना। लोकसभा चुनाव से पहले एक ओर जहां विपक्षी पार्टियां भाजपा को उखाड फेंकने को लेकर एकजूट होने का कोशिश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए भी अपनी ताकत दिखाने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में एनडीए की तरफ से 18 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होने को लेकर अब रालोजद प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी निमंत्रण दे दिया गया है। नई दिल्ली में मंगलवार को एनडीए की होने वाली बैठक को लेकर उपेन्द्र कुशवाहा ने ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम न फैलाएं। कल एनडीए की बैठक में मैं शामिल रहूंगा। निमंत्रण कल ही मिल चुका है। इसके पहले उपेन्द्र कुशवाहा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए पूरे मामले पर संशय बरकरार रखा था। उन्होंने कहा था कि हर चीज की जानकारी मीडिया को दी जाए, ये जरूरी नहीं है। मैं क्या करने वाला हूं, इसका खुलासा वक्त से पहले मीडिया के जरिए किया जाए, ये जरूरी तो नहीं है। इसके बाद कुशवाहा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब बहुत कम दिन बचा है। ऐसे में सभी लोग अपनी रणनीति बनाने को सोच रहे हैं। हम लोग भी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। अब इसी कड़ी में भाजपा भी दिल्ली में बैठक कर रही है, इस बैठक में शामिल होने को लेकर मुझे फोन पर निमंत्रण दिया गया है।

समान नागरिक संहिता पर फूंक-फूंक कर कदम रख रही कांग्रेस

विधेयक के मसौदे को जांच-परख कर तैयार करेगी आगे की रणनीति

नईदिल्ली। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी के कानूनी सलाहकारों की शनिवार को बैठक हुई। एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने यूसीसी के संबंध में पार्टी नेतृत्व को एक सूक्ष्म रुख की सिफारिश करने का संकल्प लिया। यह निर्णय लिया गया कि पार्टी विधेयक के मसौदे की पूरी तरह से जांच करने के बाद अपनी स्थिति तैयार करेगी, बशर्ते सरकार संसद में ऐसा कानून पेश करे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम, सलमान खुर्शीद और अभिषेक सांघवी उन कुछ लोगों में शामिल थे, जिन्होंने यूसीसी के कानूनी और सामाजिक पहलुओं पर चर्चा के लिए मुलाकात की।

कांग्रेस ने इस महीने की शुरुआत में यूसीसी पर अगला कदम उठाने और एक मसौदा विधेयक लाने के लिए भाजपा सरकार का इंतजार करने का फैसला किया था। इसने विधेयक के अभाव में इस विचार के विरोध में जल्दीबाजी करने से परहेज किया था। बैठक में भाग लेने वाले नेताओं ने कहा कि पार्टी एकरूपता के विचार का विरोध करती है और यूसीसी को विविधता पर हमला मानती है। हम विरासत की समानता जैसे पहलुओं का समर्थन करेंगे। लेकिन हम एकरूपता थोपने का विरोध करेंगे. सब कुछ सरकार की मंशा पर निर्भर करता है। हमें यह देखना होगा कि क्या सरकार व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के प्रति ईमानदार है या क्या वह चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ समुदायों को लक्षित करने के लिए एक विधेयक लाएगी।

यह पूछे जाने पर कि कांग्रेस कैसे सूक्ष्म रुख अपनाएगी, एक नेता ने कहा, हम कुछ प्रावधानों का समर्थन कर सकते है। लेकिन कुल मिलाकर हम एकरूपता थोपने के किसी भी प्रयास का विरोध करेंगे क्योंकि यह हमारे बहुलवादी मूल्यों और विविधता के विचार के खिलाफ है। हालांकि केंद्र ने अभी तक यह संकेत नहीं दिया है कि वह यूसीसी पर विधेयक कब लाएगी, विपक्षी खेमा पहले से ही इस मुद्दे पर बंटा हुआ है। आप और शिवसेना (यूबीटी) सैद्धांतिक रूप से इस विचार का समर्थन कर रहे हैं।

बसपा ने भी कहा है कि वह यूसीसी का विरोध नहीं करती है, लेकिन तर्क दिया है कि वह जिस तरह से भाजपा इसे लागू करने की कोशिश कर रही है का समर्थन नहीं करती है।

इससे पहले जून में, भारत के 22वें विधि आयोग (एलसीआई) ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर जनता और धार्मिक संगठनों से विचार मांगे थे। आयोग द्वारा जारी एक सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि इच्छुक और इच्छुक लोग 30 दिनों के भीतर अपने विचार और राय प्रस्तुत कर सकते हैं। समान नागरिक संहिता, संविधान के तहत एक निदेशक सिद्धांत, व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा। यह विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है। वर्तमान में, विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून काफी हद तक उनके धर्म द्वारा शासित होते हैं।

यूसीसी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी कहा मुसलमान हैं निशाना

ऑल इंडिया मजलिए-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख हैं। वे लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी से मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा।

खेल
प्रमुख समाचार

जर्मनी दौरे की शुरुआत निराशाजनक, भारतीय टीम चीन से 2-3 से हारी

लिम्बर्ग। भारतीय महिला हॉकी टीम के जर्मनी दौरे की शुरुआत निराशाजनक रही जब टीम को चीन के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। रविवार रात हुए मुकाबले में भारत के लिए नवनीत कौर ने 24वें और 45वें मिनट में गोल दागे जबकि चीन के लिए चेन जियाली (नौवें मिनट), झोंग जियाकी (45वें मिनट) और शू येनान (51वें मिनट) ने गोल किए। दोनों टीम ने पहले क्वार्टर में सतर्क शुरुआत की। भारत को तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन चीन की रक्षा पंक्ति ने इसे नाकाम कर दिया। इसके कुछ मिनट बाद भारत ने फाउल करके विरोधी टीम को पेनल्टी स्ट्रोक का मौका दिया। चीन ने इसका फायदा उठाकर जियाली के गोल की बदौलत नौवें मिनट में बढ़त हासिल कर ली।

अगले कुछ मिनट में दोनों टीम को पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन कोई भी टीम इनका फायदा नहीं उठा सकी। भारत ने दूसरे क्वार्टर में सकारात्मक शुरुआत की। टीम को लगातार दो पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन टीम इनको भुनाने में विफल रही। नवनीत ने 24वें मिनट में मैदानी गोल दागकर भारत को बराबरी दिलाई। नवनीत ने 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागकर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। चीन ने हालांकि तुरंत बाद झोंग के पेनल्टी कॉर्नर पर दागे गोल से बराबरी हासिल कर ली। येनान ने 51वें मिनट में एक और गोल दागकर चीन को 3-2 से आगे किया जो निर्णायक स्कोर साबित हुआ। भारत मंगलवार और गुरुवार को अब जर्मनी से दो मैच खेलेगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा निफ्टी 19700 पार

नई दिल्ली। पिछले हफ्ते की रिकॉर्ड तेजी के बाद इस हफ्ते भी बाजार की उड़ान जारी है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी बुल्स के पावर के आगे बीयर्स हथियार डालते नजर आ रहे हैं। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी एक बार फिर नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। सोमवार को सेंसेक्स में 550 से अधिक अंकों की बढ़त दिखी और यह 66,611.36 अंकों के लेवल के पार पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर, निफ्टी पहली बार 19700 के लेवल के पार पहुंच गया। बाजार में आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में बढ़िया खरीदारी दिख रही है। मीडिया पैक के शेयर दो प्रतिशत तक उछले हैं। सोमवार को सेंसेक्स 529.03 (0.80त्न) अंकों की उछाल के साथ 66,589.93 अंकों के लेवल पर जबकि निफ्टी 155.15 (0.79त्न) अंकों की तेजी के साथ 19,719.65 अंकों के रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ। बाजार में बंपर तेजी के बीच सोमवार को फिर सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई को छुआ।

पहली छमाही में भारत से कम हुआ विदेश में निवेश

नईदिल्ली। भारत का आउटवर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 की पहली छमाही (जनवरी से जून)में घटकर 11.12 अरब डॉलर रह गया है, जो कैलेंडर वर्ष 2022 की समान अवधि में 23.57 अरब डॉलर था। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों से यह जानकारी मिलती है। आउटवर्ड एफडीआई में कुल वित्तीय प्रतिबद्धताओं के 3 घटक इक्विटी, ऋण और गारंटी शामिल होते हैं। 2023 के अप्रैल जून के दौरान प्रतिबद्धताओं में तेज कमी आई है। यह अप्रैल 2023 में घटकर 2.52 अरब डॉलर रह गया, जो अप्रैल 2022 में 4.03 अरब डॉलर था। मई में यह 1.29 अरब डॉलर (मई 2022 में 4.04 अरब डॉलर था) और फिर जून 2023 में और घटकर 0.97 अरब डॉलर (जून 2022 में 1.93 अरब डॉलर था) रह गया। बैंक आफ बड़ौदा में मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का पता चलता है।

देश में 'अतिरिक्त लाभ' कमाने वाली कंपनियों पर बढ़े टैक्स

नईदिल्ली। भारत जी-20 की बैठक में संबंधित देश में 'अतिरिक्त लाभ' कमाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेगा और इस समूह के साझेदार देशों का समर्थन प्राप्त करेगा। यह जानकारी सरकारी अधिकारी ने दी। भारत के इस प्रस्ताव के पहले सूचना नहीं दी गई है। गुजरात में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों की बैठक में लंबे समय से प्रस्तावित वैश्विक कारपोरेट कर को दुरुस्त करने पर प्रगति हो सकती है लेकिन जी 20 के सदस्य देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया और जापान इस आशावादी कदम पर असर डाल सकते हैं। अनुमान है कि 140 से अधिक देश 2021 के समझौते को अगले साल से लागू करना शुरू कर सकते हैं। इस समझौते में एक दशक पुराने नियमों कैसे सकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाएं का संशोधन किया गया है। वर्तमान समय में पुराने नियमों को अप्रासंगिक माना जा रहा है।

विकसित देश कर रहे डीपीआई का विरोध!

नईदिल्ली। भारत के यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) को ज्यादा देश स्वीकार कर रहे हैं वहीं जी-20 में भारत के वैश्विक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ढांचे के प्रस्ताव को कुछ विकसित देशों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि यह वैश्विक प्राइवेट पेमेंट प्रॉसेसर्स के विकास में बाधा पैदा कर सकता है। भारत के यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस व्यवस्था को हाल में कई देशों ने स्वीकार किया है। इस साल मार्च में सिंगापुर की भुगतान व्यवस्था के एकीकरण के बाद पिछले सप्ताह संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के साथ समझौते हुए हैं। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 में एक ब्लॉग में कहा था कि दोनों अमेरिकी कंपनियां भारत में बाजार हिस्सेदारी गंवा रही हैं क्योंकि भारत में विकसित भुगतान व्यवस्था यूपीआई और रुपे कार्ड का प्रसार हो हो रहा है।

बीमा क्षेत्र को बदल देगा संशोधित विधेयक

मधुरेंद्र सिन्हा

अब जबकि संसद का मानसून सत्र आ चला है, कई विधेयकों पर सभी की नजर है, जिनमें कुछ ऐसे भी हैं, जो आर्थिक, वित्तीय और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इनमें एक ऐसा विधेयक है, जिसे सुधारवादी ही नहीं, रोजगार प्रेरक माना जा रहा है। यह बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2023 है और पारित होने पर यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके पारित होने पर बड़े पैमाने पर रोजगार के रास्ते खुलेंगे और निवेश भी बढ़ेगा। इसे इसी सत्र में रखा जाएगा और लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का बहुमत होने के कारण इसका पारित होना तय ही है। उम्मीद है कि इसे राज्यसभा में भी पारित होने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी।

यह विधेयक 1938 में बने बीमा कानून में संशोधन तो करेगा ही, 1999 के बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कानून में भी बदलाव लाएगा। इस संशोधन के बाद यह कानून बड़े उद्यमों तथा बीमा कंपनियों के लिए भी फायदेमंद होगा। सरकार का मानना है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बीमा और स्वास्थ्य सुरक्षा क्षेत्र में बड़ी तादाद में नई कंपनियां उतरेंगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होगा।

विकसित देशों की तुलना में भारत में बहुत कम लोग व्यक्तिगत बीमा के अंदर आते हैं। लेकिन सरकार के प्रयासों और आर्थिक मदद की वजह से 2021 तक 51 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य बीमा हो चुका था। और इस मद में बीमा उद्योग की सकल प्रीमियम आय 470 अरब रुपये थी। भारत वैश्विक स्तर पर दुनिया का नवां बीमा प्रीमियम बाजार है, लेकिन देश की आबादी का महज 3.30 फीसदी ही जीवन बीमा के

दायरे में है। इसे ध्यान में रखकर बीमा नियामक आईआरडीएआई ने 2047 तक सभी के लिए बीमा का मिशन शुरू किया है, जिससे बीमा पैठ में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी तथा क्षेत्र को अधिक निवेश-अनुकूल बनाने में सहायता मिलेगी। इससे 2027 तक ही भारतीय बीमा बाजार के 200 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी भारत में महज 24 जीवन बीमा कंपनियां हैं और 31 सामान्य बीमा कंपनियां काम कर रही हैं। इस विधेयक के पारित होने के बाद सामान्य कंपनियां भी बीमा के कारोबार में कदम रख सकती हैं।

यह विधेयक इस दृष्टि से अनूठा है कि इसमें बीमा कंपनी खोलने के लिए बाध्यकारी 100 करोड़ रुपये की सीमा को खत्म किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक कारोबारी इस क्षेत्र में कदम रख सकें। अब भारत में जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा एक साथ हो सकेंगे, जिससे बीमाधारक को बड़ी-बड़ी हेल्थ कंपनियों की सेवाएं बीमा के पैसे से ही मिल सकेंगी। अमेरिका-यूरोप में ऐसी व्यवस्था पहले से है। भारत में सरकार इस क्षेत्र में काम कर रही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का काम शुरू कर चुकी है। इससे इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए रास्ता खुलेगा।

संसद के मानसून सत्र में इस बार कई और भी विधेयक रखे जाएंगे, जिनमें कंपनियों के दिवालिया होने पर आगे उनके अधिग्रहण को आसान बनाने के लिए भी एक विधेयक है, जिससे समय बर्बाद नहीं होगा और पुरानी कंपनी को कोई नई कंपनी अपने हाथ में ले सकेगी। दरअसल, यह 2016 में बनाए गए इंसॉल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में संशोधन है, जिससे दीवालियापन की प्रक्रिया में तेजी आए और सबसे उपयुक्त दावेदार को शीघ्र उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि संपत्ति बर्बाद न हो। इस बार कर कानूनों में संशोधन से भी जुड़ा विधेयक रखा जाएगा, जिससे टैक्स देने वालों को आसानी होगी और जटिलता खत्म होगी। लेकिन संसद के पिछले सत्र में हमने देखा कि विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस ने इतना हंगामा किया कि दोनों सदनों के कामकाज में बहुत बाधा पहुंची और कई सारे बिल धरे रह गए। कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और वह संसद में हंगामे के लिए तैयार है। इसके लिए वह मणिपुर में हुई हिंसा को मुद्दा बनाएगी।

चांद सभी का तो चंद्रयान क्यों नहीं

अभिनय आकाश

चंद्रमा एक ऐसा खास आकर्षण जिसने सदियों से हमारे मन और कल्पनाओं पर अधिकार जमाया हुआ है। हमारे अतीत की कुंजी और भविष्य की ओर ले जाने वाला मार्ग। हम सब के बचपन में चांद से जुड़ी लोरियों और कहानियों की एक अलग जगह बनी हुई है। चांद हमेशा से हमारे लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। चांद को मुट्ठी में करने सपनों की उड़ान पर हिन्दुस्तान निकल पड़ा है। 14 जुलाई 2023 की तारीख देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ। दोपहर के 2:30 मिनट पर भारत का चंद्रयान-3 चांद की ओर रवाना हो गया। चांद को छूना औरों की तरह हमारा भी सपना रहा है। चंद्रयान-3 पृथ्वी कक्षा में स्थापित हो गया। 40 दिन बाद पहले पृथ्वी और फिर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। उसके बाद चांद पर उतरेगा। अभी पृथ्वी पर भी एक नया चक्कर चल रहा है। चंद्रयान-3 के रवाना होते ही उसे लेकर क्रेडिट की लड़ाई भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इसका पूरा श्रेय वैज्ञानिकों को दिया। वहीं बीजेपी के कुछ नेताओं ने वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी इसका श्रेय दिया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से भी ताबड़तोड़ बयान आए। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, जयराम रमेश जैसे कई नेताओं ने जो ट्वीट किए उसमें लिखने का भावार्थ यही था कि इसरो की शुरुआत तो नेहरू जी ने ही की थी। उन्होंने ही तो अंतरक्षि को लेकर सपने जगाए थे वरना ये सब कैसे होता? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने नेहरू जी से लेकर अटल जी तक को क्रेडिट दिया। लेकिन मनमोहन सिंह के बाद वो मोदी का नाम लिखना भूल गए या फिर उन्होंने जान बूझकर नहीं लिखा। ये तो वही बता सकते हैं। इसके बाद ही देखते-देखते नेहरू जी और इंदिरा गांधी की कुछ पुरानी तस्वीरें अवतरित हुईं। इसरो की साइकिल पर रॉकेट ले जाती तस्वीरें वायरल होने लगी। कांग्रेस ने एक नैरेटिव गढ़ा तो वहीं काउंटर में ये दलील दी जाने लगी कि मोदी न होते तो आज भी साइकिल पर ही रॉकेट ले जा रहे होते। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण को सभी भारतीयों के लिए बेहद गर्व का क्षण बताते हुए कहा कि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर मनमोहन सिंह सहित पिछले सभी प्रधानमंत्रियों की दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प की उपलब्धियों का प्रमाण है। बेशक इसमें इसरो और हमारे अनगिनत वैज्ञानिकों का महान योगदान है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश में वैज्ञानिक सोच के लिए समर्पित कर दिया। रोचक तथ्य यह है कि इसमें मोदी सरकार के नौ साल के कार्यकाल का कोई जिक्र नहीं किया गया। नेतृत्व की नीति और इच्छाशक्ति को भी देखना जरूरी है। 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5 हजार 400 करोड़ रुपए थे। भारत के विज्ञान को हम इससे किस दिशा में ले जा सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सारे पैसे वेतन और लैबोरेट्री के मेंटेनेंस में ही चले जाते थे। लेकिन 2022 में 14 हजार 217 करोड़ हो गया है। यानी 2014 से लेकर 2022 तक इसके बजट में तीन गुणा इजाफा हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी की सरकार में साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी को लाकर एक नई क्रांति को जन्म दिया। अगले पांच साल में भारत अमेरिका और रूस से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला है। वही वैज्ञानिक स्टालिन और जार के युग में थे। वहीं वैज्ञानिक वाशिंगटन और लिंकन के युग में भी थे। दोनों का काम अलग अलग था।

यादव अब सपा के साथ नहीं रहे

अजय कुमार

समाजवादी पार्टी पिछले करीब दस वर्षों में हार का %चौका' लगा चुकी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ हार का यह सिलसिला 2017 के विधान सभा और 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात एक बार फिर 2022 के विधान सभा में मिली हार तक जारी रहा था। हर बार सपा को भाजपा से मात खानी पड़ी। बीजेपी के सामने अखिलेश सभी दांव आजमा चुके हैं। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सपा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की चुनावी परीक्षा होगी, लेकिन इस बार भी अखिलेश की राह आसान नहीं लग रही है। अब तो अखिलेश के पास कोई नया 'प्रयोग' भी नहीं बचा है। वह कांग्रेस और बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का भी साथ करके देख लिया है, लेकिन कोई भी प्रयोग उनकी हार के सिलसिले को रोक नहीं पाया। स्थिति यह हो गई है कि आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव बिल्कुल 'तन्हा' नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तो समाजवादी पार्टी से दूरी बनाकर चल ही रहे हैं, इसके अलावा उसके मौजूदा साथी राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी जयंत सिंह और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी भाजपा गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश का साथ उसके सहयोगी ही नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि कई पुराने नेताओं ने भी किनारा कर लिया है। वह मुसलमान नेता भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं जो कभी मुलायम सिंह को अपना रहनुमा समझते थे, लेकिन अखिलेश से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसमें कई नेता ऐसे हैं जो मुलायम के काफी करीबी थे। बीते वर्ष अक्टूबर में तो मुस्लिम बाहुल्य जिला संभल में सपा को इतना तगड़ा झटका लगा कि उसकी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के पूर्व चेयरमैन हाजी आजम कुरैशी का सपा से ही मोहभंग हो गया है। कुरैशी ने सपा की साइकिल से उतरकर बीजेपी का दामन थाम लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर कुरैशी बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद और मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए हाजी आजम कुरैशी तो यहां तक आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश अपने दफ्तर में बैठकर सिर्फ ट्वीट करने का काम करके मुसलमानों को बीजेपी से डर दिखा रहे हैं, लेकिन मुसलमान हकीकत समझ गया है कि कौन मुसलमानों के साथ है और कौन उनके लिए घड़ियाली आंसू बहाता है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुसलमानों की नाराजगी की वजह पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि मुसलमानों को अखिलेश से सबसे बड़ी यही नाराजगी है कि सपा प्रमुख मुसलमानों के समर्थन में नहीं बोल रहे हैं। मुस्लिम वर्ग का कहना है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ अखिलेश कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहां तक कि मुसलमानों की समस्याओं और उत्पीड़न के खिलाफ अखिलेश शायद ही कभी मुंह खोलते हों। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के गठन के समय मुलायम सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आजम खान की अनदेखी भी अखिलेश पर भारी पड़ रही है। कुछ राजनैतिक जानकार कहते हैं कि मुसलमानों की नाराजगी बेवजह नहीं है, वह चाहते थे कि विधानसभा में आजम खान को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाये। इसके पीछे का तर्क देते हुए मुसलमानों का कहना था कि अगर सपा चुनाव जीत जाती तो अखिलेश मुख्यमंत्री बनते, लेकिन हार के बाद तो कम से कम आजम को उचित सम्मान दिया जाता। मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के एक बड़ी वजह यह भी है। चुनाव के समय मुसलमान वोटर तो सपा के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं, लेकिन सपा के कोर यादव वोटर्स अखिलेश से किनारा कर रहे हैं। पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर नेताओं का कहना है कि चुनाव में मुस्लिमों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया, लेकिन सपा के यादव वोटर्स ही पूरी तरह से उनके साथ नहीं आए। इसके चलते चुनाव में हार मिली। इसके बाद भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश का नहीं बोलना नाराजगी को बढ़ा रहा है।

बात पार्टी से नाराज चल रहे समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं की कि जाए तो इसमें सांसद डॉ. शफीकुर्ररहमान बर्क से लेकर तमाम नेता शामिल हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. शफीकुर्ररहमान बर्क अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि भाजपा के कार्यों से वह संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा सरकार मुसलमानों के हित में काम नहीं कर रही है। फिर वह तंज कसते हुए कहते हैं कि भाजपा को छोड़िए समाजवादी पार्टी ही मुसलमानों के हितों में काम नहीं कर रही। सपा के सहयोगी रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉ. मसूद ने 2022 में विधान सभा चुनाव नतीजे आने के कुछ दिनों बाद ही अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेज दिया था। इसमें उन्होंने रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा था। अखिलेश को तानाशाह तक कह दिया था। सपा पर टिकट बेचने का आरोप भी लगाया था।

इसी दौरान इमरान मसूद और सहारनपुर के सपा नेता सिकंदर अली ने पार्टी छोड़ दी। पार्टी छोड़ते हुए सिकंदर ने कहा कि हमने दो दशक तक सपा में काम किया। सपा अध्यक्ष कायर की तरह पीठ दिखाने का काम कर रहे हैं। मुस्लिमों की उपेक्षा की जा रही है। सिकंदर ने कहा कि सपा के बड़े-बड़े मुस्लिम नेता जेलों में बंद हैं लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी पीड़ा पहुंचाने वाली है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड सहारनपुर के जिला उपाध्यक्ष अदनान चौधरी भी अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अदनान चौधरी का कहना था कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादव की चोंच बिल्कुल बंद है।

हाल ही में सुल्तानपुर के नगर अध्यक्ष कासिम राईन ने भी अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने में कोई रुचि नहीं है। आजम खां का पूरा परिवार जेल में डाल दिया गया पर अखिलेश यादव नहीं बोले। नाहिद हसन को जेल में डाल दिया गया और शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया गया लेकिन सपा अध्यक्ष ने इस पर आवाज नहीं उठाई। सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे इरशाद खान ने भी मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुसलमानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इरशाद ने कहा कि मुसलमान हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। लेकिन उसे सत्ता और संगठन में सम्मानजनक भागीदारी नहीं मिल पाई। समाजवादी पार्टी युवजन सभा बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद हमजा शेख भी पार्टी छोड़ चुके हैं। हमजा शेख ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों से कतराते हैं। वह मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों को देखकर भी चुप रहते हैं। मुस्लिमों को लेकर कोई आंदोलन नहीं करते। सिर्फ ट्विटर पर ही राजनीति करते हैं।

उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नब्बे के दशक तक उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। तब तक यूपी में कांग्रेस मजबूत स्थिति में रही, लेकिन, राम मंदिर आंदोलन के चलते मुस्लिम समुदाय कांग्रेस से दूर हुआ तो सबसे पहली पसंद मुलायम सिंह यादव के चलते सपा बनी और उसके बाद समाज ने बसपा को अहमियत दी। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच मुस्लिम वोट बंटता रहा, लेकिन 2022 के चुनाव में एकमुश्त होकर सपा के साथ गया। मुसलमानों का सपा के साथ एकजुट होने का फायदा अखिलेश यादव को मिला। सपा 47 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 83 फीसदी मुस्लिम सपा के साथ थे। बसपा और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों को भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया था। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी मुस्लिमों ने नकार दिया था। इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय ने किसी एक पार्टी को 1984 चुनाव के बाद वोट किया था। यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमान वोटर एकजुट रहा तो सूबे की 26 लोकसभा सीटों पर सियासी उलफेर हो सकता है। ऐसे में मायावती निकाय चुनाव के जरिए दलित-मुस्लिम समीकरण फिर से लौटी हैं तो कांग्रेस भी अपनी तरफ उन्हें लाने की कोशिश कर रही है। वहीं, बीजेपी पसमांदा कार्ड के जरिए मुस्लिमों के बीच अपनी जगह बनाना चाहती है तो असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम लीडरशिप के बहाने सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बात सपा की कि जाए तो भले ही पार्टी के मुस्लिम नेता अखिलेश का साथ छोड़ रहे हों, परंतु सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को लेकर बेफिक्र हैं। अखिलेश यादव को यकीन है कि यह वोट फिलहाल उनसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे में देखना है कि भविष्य की सियासत में मुस्लिम मतदाता किसके साथ खड़ा नजर आता है। उधर, मुस्लिम समुदाय को लेकर उत्तर प्रदेश में की जा रही सियासत पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर कहते हैं कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया है, बीजेपी के साथ हो गया है। समाजवादी की जब सत्ता रही तब ना मुस्लिम सीएम बनाया, ना डिप्टी सीएम बनाया और ना मुस्लिम को सरकारी नौकरी दिलाई।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

त्रिशिखिब्राह्मणोपनिषद् (भाग-9)

गतांक से आगे...

जो मनुष्य इस तरह लगातार तीन वर्ष तक नियमित अभ्यासपूर्वक प्राणायाम करता है, वह योगसिद्ध हो जाता है। वह योगी (साधक) वायु को जीतने वाला, इन्द्रियों को अपने वश में रखने वाला, अल्पाहारी, स्वल्प नींदवाला, तेजोमय एवं बलवान् होता है। वह अकाल मृत्यु के भय को विनष्ट करके दीर्घायु को प्राप्त होता है। जिस प्राणायाम में पसीना आता है, वह अधम कहलाता है। जिस (प्राणायाम) में शरीर में कँपकँपी होती है, वह मध्यम है तथा जिस (प्राणायाम) में शरीर ऊर्ध्व की ओर उठता है, वह उत्तम कहा गया है।

अधम कोटि के प्राणायाम से आधि-व्याधि एवं सम्पूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। मध्यम कोटि के प्राणायाम से महाव्याधियाँ, पाप एवं समस्त रोग समाप्त हो जाते हैं और उत्तम प्राणायाम से (साधक) अल्पनिद्रा वाला, अल्प मल-मूत्र वाला, लघु शरीर वाला एवं अल्पाहार वाला होता है। इन्द्रियाँ एवं बुद्धि तीव्र हो जाती हैं तथा वह योगी तीनों कालों को जानने में समर्थ हो जाता है। जो योगी रेचक एवं पूरक से मुक्त होकर एकमात्र कुम्भक ही करने में तत्पर हो जाता है, उसके लिए तीनों कालों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता।

अपने योग में निरन्तर प्रयत्नशील रहने वाले साधक को नाभिकन्द (मूल) में नासिका के अग्रभाग में तथा दोनों पैरों के अँगूठे में, सन्ध्या-वन्दन के समय मन द्वारा प्राणतत्त्व की धारणा करनी चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया से योगी साधक समस्त रोगों से मुक्त होकर आनन्दपूर्वक जीवन पूर्ण करता है। नाभिकन्द (मूल) में प्राणों को धारण करने पर कुक्षि (कोख पेट) के समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं। नासिका के अग्रभाग में प्राण को धारण करने से दीर्घायुष्य एवं शरीर की लघुता (हल्कापन) प्राप्त होती है। ब्राह्ममुहूर्त में जिह्वा द्वारा वायु को खींचकर पीने से मात्र तीन मास में ही वाक् सिद्धि प्राप्त हो जाती है तथा छः मास में (उस योगी को) महारोग से मुक्ति मिल जाती है। शरीर के पीड़ित अंगों में जहाँ तहाँ वायु के जकड़न आदि से उत्पन्न दूषित रोगों का विनाश करने के लिए उन अंगों में वायु (प्राण) को धारण करने से योगी रोग रहित हो जाता है। मन की धारणा से ही वायु (प्राण) की भी धारणा उत्पन्न होने लगती है। हे द्विज! मन को स्थिर एकाग्र करने के लिए प्राण की साधना (प्राणायाम) को अनिवार्य कहा गया है।

क्रमशः ...

नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस

नेल्सन मंडेला दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने 2009 में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता नेल्सन मंडेला को सम्मानित करने के लिए 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में घोषित किया था, जिन्होंने 1994 से 1999 तक पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। मंडेला राज्य के पहले अश्वेत प्रमुख थे और दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनाव में पहले निर्वाचित राष्ट्रपति थे। यह दिन दक्षिण अफ्रीका में बहुजातीय लोकतंत्र को हराने के लिए उनके संक्रमणकालीन कदमों को भी उजागर करेगा।

अन्याय के अंधकार का अंत करके न्याय का राज स्थापित करने वाले नेल्सन मंडेला ने 67 साल तक अनेकों यातनाओं को सहा। नेल्सन मंडेला के जीवन से समाज को प्रेरणा मिले इसके लिए ही आधिकारिक तौर पर नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। पहली बार 18 जुलाई 2009 को मनाया गया था।

नेल्सन मंडेला दिवस मानव जाति की सेवा करने और उन लोगों के लिए काम करने के महत्व को दर्शाता है जो अपने दम पर नहीं लड़ सकते हैं। मंडेला दिवस कार्रवाई के लिए एक वैश्विक आह्वान है जो इस विचार का जश्न मनाता है कि प्रत्येक व्यक्ति में

बदलाव लाने और समाज पर प्रभाव डालने की शक्ति है। यह दिन दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की विरासत को सम्मानित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस दिन को '46664' के रूप में भी जाना जाता है और मूल रूप से एचआईवी / एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया था।

नवंबर 2009 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने समाज में शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति के योगदान को मान्यता देने के लिए 18 जुलाई को 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में घोषित किया। वह न केवल लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, बल्कि दुनिया को बदलने के लिए विशाल सपनों वाले व्यक्ति भी थे।

यह दिन गरीबी, लिंग असमानता, नस्लवाद और मानवाधिकारों के उन्मूलन के खिलाफ उनकी लड़ाई को स्वीकार करता है। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव ए/आरईएस/64/13 मंडेला के मूल्यों और मानवता की सेवा के लिए उनके आजीवन समर्पण का उल्लेख करता है।

नेल्सन मंडेला के विचार

जब मैं बातचीत कर रहा था तब मैंने जो कुछ सीखा वह यह था कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। संसार में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे लोगों पर निर्भर है कि वे सही पक्ष का चुनाव करें। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनौती देना है। मैं अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सोना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो पीछे रह जाते हैं, वे यह कहें कि इस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। आज़ादी की राह कहीं भी आसान नहीं है, और हममें से कई लोगों को अपनी इच्छाओं के पहाड़ पर पहुँचने से पहले बार-बार मौत की छाया की घाटी से गुज़रना होगा। मुक्त होने का अर्थ केवल अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और उसे बढ़ाए। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि और भी बहुत सी पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं।

फ्रांस की मदद से बढ़ती भारत की सैन्य क्षमता

ले. जनरल (रिटा.) संजय कुलकर्णी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे में हुए महत्वपूर्ण समझौतों से पहले वायुसेना को फ्रांस से 36 रफाल विमान ऐसे समय मिले, जब हमें इनकी सख्त जरूरत थी। तीन साल पहले पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों के बाद रफाल के आने से उसे समझ आ गया कि भारत की सैन्य शक्ति बढ़ गयी है। इसी तरह अभी तीन और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों की खरीद का जो समझौता हुआ है, उससे भी चीन को एक संदेश गया है।

चीन दक्षिण-चीन सागर और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। दक्षिण-चीन सागर के लगभग 90 फीसदी हिस्से पर उन्होंने नियंत्रण कर लिया है। वहीं हिंद-प्रशांत क्षेत्र में फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देश चीन की बढ़ती ताकत देख उसके खिलाफ कुछ बोलने से बचते हैं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए समुद्री जल क्षेत्र में भी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। भारत को अभी 30 पनडुब्बियों की जरूरत है।

फ्रांस के साथ हुए सौदे के बाद भारत के पास 16 से 18 पनडुब्बियां हो जायेंगी। इनसे भारत की रक्षात्मक शक्ति बढ़ेगी। ऐसे में, फ्रांस से पहले मिले 36 रफाल और अब तीन और स्कॉर्पीन पनडुब्बियों का सौदा काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री के फ्रांस के दौरे से पहले 26 और रफाल विमानों के सौदे की चर्चा थी। हालांकि, संभवत: कीमत को लेकर मोल-तोल की वजह से उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, मगर बातचीत चल रही है और सौदे को डीएसी यानी

रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिल गयी है। साथ ही, फ्रांस ने अपने ऐसे दो-तीन रफाल ट्रेनिंग के लिए देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे उम्मीद है कि ये विमान भारत को जरूर मिलेंगे।

ये 26 नये विमान मरीन रफाल हैं, यानी नौसेना के लिए हैं, जो विमानवाहक युद्धपोत विक्रांत के लिए आयेंगे। ये खास जहाज बहुत छोटी हवाई पट्टी से उड़ान भर सकते हैं। ये हल्के भी हैं और मजबूत भी। इनके विंग्स फोल्डेबल हैं। ये केवल 10 मीटर जगह घेरते हैं। इनकी तुलना में, अभी जिन मिग-29 विमानों का इस्तेमाल होता है, वे 13 मीटर जगह लेते हैं। ऐसे में, विक्रांत पर ज्यादा संख्या में युद्धक विमानों को तैनात किया जा सकेगा।

वायुसेना के एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। नये 26 विमानों में 18 विमान विक्रांत पर तैनात रहेंगे। अन्य विमान गोवा में रहेंगे, जिन पर ट्रेनिंग दी जायेगी। इनसे स्थल और समुद्री मोर्चे पर भारत की सैन्य क्षमता बढ़ेगी। फ्रांस और भारत के बीच पांच साल पहले समुद्री मोर्चे से संबंधित एक रणनीतिक साझेदारी हुई थी। इनके तहत हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में मौजूदगी बढ़ायी जानी है, क्योंकि चीन वहां अंतरराष्ट्रीय नियमों को लगातार तोड़ता रहा है।

इसी संधि के तहत भारत को स्कॉर्पीन पनडुब्बियां मिली हैं, जो काफी गहराई में हफ्ते-दस दिन तक रह सकती हैं। ये जहाजों और टॉरपीडो को नष्ट कर सकती हैं। ऐसे में जब ये पनडुब्बियां भारत के आस-पास हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गश्त लगाती हैं, तो चीन के भारत को समुद्र में घेरने की रणनीति के खिलाफ एक सुरक्षा कवच तैयार होता है।

चीन एक ओर श्रीलंका के हंबनटोटा में, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के ग्वादर में या फिर म्यांमार के पास कोको द्वीप पर पैर जमाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल, किसी भी तरह की सुरक्षा के लिए आंख और कान खुला रखना बहुत जरूरी है। मगर, समुद्र का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इस काम में स्कॉर्पीन पनडुब्बियों और रफाल के मरीन युद्धक विमानों से बहुत मदद मिलेगी।

स्कॉर्पीन सौदे का एक और लाभ यह है कि इन्हें हम खुद बनायेंगे। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में पहले से ही कई सालों से छह पनडुब्बियां बन रही हैं और उनके बनने के बाद वहां तीन और पनडुब्बियों को बनाया जायेगा। इससे उनका कौशल और क्षमता बढ़ेगी, जिसका फायदा होगा, क्योंकि भारत को 30 पनडुब्बियों की जरूरत है और अभी हमारे पास 16-18 पनडुब्बियां ही हैं।

साथ ही, भारत ने फ्रांस की एक बड़ी विमान इंजन निर्माता कंपनी साफरान के साथ साझा-उत्पादन का एक समझौता किया है। इसके तहत डबल इंजन वाले एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या एएएमसीए और इंडियन मल्टीरोल हेलिकॉप्टर या आइएमआरएच के इंजन भारत में बनाये जायेंगे। ये पांचवीं और छठी जेनरेशन के अत्याधुनिक इंजन हैं यानी ये पूरी इक्कीसवीं सदी तक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं।

पिछले महीने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी कंपनी जीई के साथ तेजस विमानों के जी-413 इंजन के भारत में ही साझा-निर्माण के लिए समझौता हुआ था। उसमें तकनीक के 80 फीसदी ट्रांसफर पर सहमति हुई थी, मगर फ्रांसीसी कंपनी के साथ समझौते में 100 प्रतिशत तकनीक ट्रांसफर होगी, यानी इंजन बनाने की पूरी तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी।

तकनीक ट्रांसफर का विषय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एक बार विमान या सैन्य साजो-सामान मिल गये, तो उनके नियमित रखरखाव और मरम्मत की आवश्यकता होती है। अभी रफाल और अन्य साजो-सामान देने वाली कंपनियां भारत में ही प्लांट लगायेंगी, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सह-उत्पादन का मतलब है कि ये विमान और इंजन भारत में ही बनेंगे। ऐसे में, भारत रक्षा-उत्पादों का निर्यातक भी बन सकेगा।

बापू की दिनचर्या

प्रवचन और हरिजन सेवा (भाग-2)

गतांक से आगे...

उन्होंने बापू से आश्रम का समस्त कार्य राष्ट्रभाषा हिंदी में चलाने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया और तभी से आश्रम एवं प्रार्थना- प्रवचन की भाषा हिंदी बन गई। बापू की प्रार्थना सभा जनसाधारण को शिक्षित करने एवं लोकमत जागृत करने का सुंदर साधन था। इसकी पूर्ति समाचारपत्रों अथवा पुस्तकों के द्वारा नहीं हो सकती। यह कार्य वे अपनी दैनिक प्रार्थना सभा से कर देते। यदा-कदा वे अपने नाम आए पत्र उस समय पढ़कर सुनाते और उनके उत्तर दे दिया करते। उनकी प्रार्थना सभा में आनेवाले अनेक महान विद्वान एवं विदेशी उनके प्रवचनों को सुनकर तथा जन-साधारण का उनके प्रति असाधारण आदर भाव देखकर चकित रह जाते। सायंकालीन प्रार्थना-प्रवचन के अनंतर बापू हरिजन-कोष के लिए झोली फिरवाया करते। इससे प्रतिवर्ष लगभग दो लाख रुपयों की आय हो जाती। उसी समय उनके निकट हस्ताक्षर करानेवालों का झुंड पहुँच जाता। हस्ताक्षर-शुल्क पाँच रुपया लेते। यह आय हरिजन-कोष में जमा होती। एक बार एक श्रद्धालु ने उनको हस्ताक्षर-शुल्क-स्वरूप पाँच सौ रुपयों का चेक भेंट किया था। रेल यात्रा में भी बापू का यह क्रम चलता। उस समय जब वे जनता को दर्शन देने के लिए खिड़की पर आते तब चंदा प्राप्त करने के लिए हाथ फैला दिया करते। हरिजन-यात्रा के समय (सन् 1934) से यह क्रम शुरू हुआ और अंत तक जारी रहा। यदा-कदा ऐसा होता कि बापू कुछ लिख रहे हैं कि स्टेशन आ गया तो लेखन जारी रखते हुए वे एक हाथ खिड़की से बाहर निकालते और बिना कुछ कहे देखते-देखते रुपयों तथा छोटे-मोटे गहनों का ढेर लग जाता। बाद में वे आभूषण नीलाम कर दिए जाते। प्यारेलालजी के शब्दों में बापू का यह पुराना रिवाज था। इस प्रकार देश की जनता मानो साक्षात् दरिद्रनारायण की पूजा करती। बापू अस्पृश्यता का आरंभ से अंत तक विरोध करते रहे।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

विधानसभा का मानसून सत्र आज से, 13 मंत्री 550 प्रश्नों का करेंगे सामना

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसूत्र सत्र कल से शुरु हो रहा है इस दौरान 13 मंत्री 550 प्रश्नों का सामना करते हुए सदन में जवाब प्रस्तुत करेंगे। मानसूत्र सत्र 21 जुलाई तक चलेगा, इस दौरान सरकार तीन हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करेगी वहीं अंतिम दिन विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। आज पहले दिन भाजपा विधायक विद्या रतन भसीन को श्रध्दांजलि के बाद सदन बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। उसके बाद तीन दिन सदन में हंगामे के बीच कार्रवाई चलेगी। इस दौरान 13 मंत्री 550 प्रश्नों का सामना करेंगे। वहीं सरकार की तरफ से तीन विधेयक की सूचना दी गई है, इतने ही और आ सकते हैं। 21 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस विधानसभा के कार्यकाल में दूसरी बार यह प्रस्ताव लाया जा रहा है हालांकि इसमें विपक्ष की हार तय है, फिर भी वह सरकार की खामियों और कथित घोटालों को सदन में सार्वजनिक करने का अवसर लेना चाह रहा है।

नारायण चंदेल ने दी हरेली तिहार की शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ का पहला तिहार हरेली धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनेता भी किसानों और प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हरेली पर्व की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को दी हैं। हरेली के दिन सभी लोग प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सदा हरियाली बने रहने की कामना करते हैं। इस दिन गांव-गांव में किसान भाई अपने घरों में अनेक प्रकार के पकवान भी बनाते हैं। जैसे गुड़ चीला, गुलगुला, चावल का फरा। छत्तीसगढ़ी मिष्ठानों का पूरा परिवार साथ बैठकर इस पकवान का आनंद भी लेते हैं। हरेली के दिन गांव-गांव में नारियल फेंकना, गेड़ी चढ़ना यह त्योहार छत्तीसगढ़ी परंपरा का जीवंत प्रमाण है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हरेली के पावन पर्व पर क्षेत्र, अंचल एवं प्रदेश के सभी किसान भाईयों आम नागरिकों को बधाई देते हुए सभी के मंगलमय जीवन की कामना की है।

वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी, एक ही दिन में दो सेक्शन में हुई घटना

भाटापारा। वंदे भारत एक्सप्रेस में पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेन में एक ही दिन दो अलग-अलग सेक्शनों में पत्थरबाजी हुई है। यह घटना राजनांदगांव और तिल्दा- हथबंद स्टेशन के बीच हुई है। अज्ञात पत्थरबाजों के खिलाफ भाटापारा और राजनांदगांव में मामला दर्ज कर आरपीएफ ने पत्थरबाजों की तलाश शुरू कर दी है।

राज्यपाल की आत्मकथा बैटल नॉट यटओवर का विमोचन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन की ओर से लिखित आत्मकथा बैटल नॉट यटओवर का आज नई दिल्ली में विमोचन किया गया। इस बायोग्राफी में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के जीवन संघर्षों और उनसे मिली सीख को शेयर किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि कहा कि मेरे रिश्तेदारों और शुभचिंतकों की प्रेरणा से यह पुस्तक इस रूप में सामने आई है। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता परशुराम हरिचंदन की देशभक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। राज्यपाल ने कहा कि वो जिस भी पद पर रहे। उन्होंने हमेशा न्याय के लिए काम किया और अन्याय के खिलाफ मुखर रहे। पुस्तक में उनके राजनीतिक संघर्षों, आपातकाल के दौरान संघर्ष, उस समय ओडिशा के राजनीतिक परिदृश्य, लोगों के कल्याण के लिए मंत्री के रूप में उनकी ओर से की गई पहल को प्रमुखता से बताया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल हरिचंदन का स्वागत किया गया। इस सेमिनार को डॉ. विजयानंद सिंह ने संबोधित किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से पुस्तक के बारे में दिए गए संदेश को पढ़ा। सेमिनार को ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गोपाल गावड़े, राष्ट्रीय कानून आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विश्वनाथ रथ, भगवान जय सिंह, और श्रीनिवास राव ने भी संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने हरेली तिहार पर अत्याधुनिक तकनीक से जन्मी बछिया की पूजा-अर्चना की

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज हरेली तिहार के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में अत्याधुनिक तकनीक से जन्मी बछिया और उसकी मां की पूजा-अर्चना की और उन्हें हरी घास, चारा और आटे की लोई खिलाई। बछिया का जन्म पिछले जून माह की 07 तारीख को लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमेन) द्वारा कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हुआ है। गौरतलब है कि हरेली तिहार पर पशुधन सहित खेती-किसानी से जुड़े औजारों की पूजा कर उनका आभार प्रगट किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा, गरवा, घुरवा, बारी को सहेजने और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गरवा योजना से पशुधन के विकास और उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री निवास में पिछले वर्ष 03 सितंबर को लिंग वर्गीकृत वीर्य के माध्यम से बछिया के लिए इंसेमिनेशन किया था। इस विधि से जन्मी बछिया ढाई साल में ही बड़ी हो जाएगी। इससे दूध भी मां की अपेक्षा अधिक मिलेगा।

कृषि हितैषी योजनाओं ने लौटाया हरेली का उत्साहः बघेल

■ **प्रदेश की संस्कृति को सहेजने के साथ ही लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करने का कार्य किया छत्तीसगढ़ सरकार ने**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने हरेली त्योहार केवल गेड़ी चढ़ने का त्योहार नहीं है। यह जीवन के उल्लास का त्योहार है। जीवन में उल्लास ऐसे ही नहीं आता। इसके लिए वातावरण बनाना होता है। हमारे प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। पिछले पौने पांच सालों में हमारी सरकार ने कृषि हितैषी नीतियां बनाईं जिससे किसान के घर खुशियां लौटीं हैं। आज हरेली के त्योहार पर जो अपूर्व उल्लास किसानों के बीच छलक रहा है उससे बहुत खुशी हो रही है। हरेली तिहार के मौके पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने किसान-मजदूर को लक्षित कर योजनाएं बनाईं। इससे कृषि का रकबा बढ़ा और अब तो प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने के निर्णय से यह उल्लास अपने चरम पर है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर होने से त्योहार का उल्लास अपने चरम पर है।

उन्होंने प्रदेशवासियों को हरेली त्यौहार की शुभकामनाएं देते हुए अच्छी फसल और किसानों की समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि हरेली में किसान अपने कृषि उपकरणों की पूजा करते हैं और पशुधन को लोंदी खिलाया जाता है। इस तरह से हम अपने पशुधन को सहेजते हैं और उनके माध्यम से हमारी तरक्की का रास्ता खुलता है। उन्होंने कहा कि आज आदिवासी क्षेत्रों में भी खुशी का माहौल है। हमारे पूर्वजों द्वारा बरसों से तैयार की गई संस्कृति नष्ट हो रही थी। इसे सहेजने-संरक्षित करने का प्रयास हमने किया है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। आदिवासी अंचल में आस्था केन्द्रों को संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। नारायणपुर में घोटुल का संरक्षण किया गया है। बस्तर के आसना में बादल के माध्यम से आदिम संस्कृति को सहेजने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे आदिवासी जीवन की परंपरा बहुत समृद्ध है। इन परंपराओं के बारे में हम सोचे तो चकित हो जाते हैं। यह ऐसी संस्कृति है जो अपने देवी-देवताओं के साथ रहती है। उनसे गहन लगाव रखती है। हमने इसे संरक्षित करने का काम किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल आरम्भ किये। इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है। रामायण मण्डलियों के माध्यम से हम लोगों के जीवन में भगवान राम का आदर्श उतारने की कोशिश कर रहे हैं। रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को बहुत लोकप्रियता मिली। चंदखुरी, शिवरीनारायण और राजिम जैसे धार्मिक केन्द्रों के साथ ही राम वनगमन पथ को विकसित करने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़िया संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के लिए हम शुरू से ही कार्य कर रहे है। मजदूरों, किसानों का परंपरागत भोजन बारे-बासी अब फाइव स्टार होटल तक पहुंच गया है। अपनी संस्कृति को सम्मान और पहचान मिलने से गौरव महसूस कर रहे हैं और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वाक्य चरितार्थ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने हरेली त्योहार के साथ प्रदेशवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री कुलदीप जुनेजा, श्री रामपुकार सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरिश देंवांगन, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक, शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामकुमार पटेल, छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष श्री नंदकुमार साय, अल्प संख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री महेंद्र छाबड़ा, सिरपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सतीश जग्गी, तेलघानी बोर्ड के अध्यक्ष श्री संदीप साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह सहित कृषि, संस्कृति व पशुधन विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

बरसते पानी में भाजपाइयों की दहाड़ उखाड़ फेंको कांग्रेस सरकार को

कबीरधाम। छत्तीसगढ़ सरकार व क्षेत्रीय विधायक पर वादाखिलाफी का आरोप और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने कबीरधाम में जमकर प्रदर्शन किया। सभा करने के बाद भाजपाइयों ने शहर में रैली निकाली। इस दौरान पूर्व संसदीय सचिव कोमल जंघेल ने कहा कि जिस लुभावने घोषणापत्र की बदौलत कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सरकार प्राप्त की थी, उसके वादों को पूरा करने में विफल रही है। भाजपा पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय विधायक के निवास और कार्यालय का घेराव कर उन्हें वादा पूरा करने प्रदर्शन कर रही है।

विधायक पर विद्वेषपूर्ण राजनीति का आरोप

भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गांधी मैदान में एकत्र हो गए। वहां हुई जनसभा में भाजपाइयों ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि कवर्धा विधायक मो. अकबर के कार्यकाल में पूरे क्षेत्र में विद्वेषपूर्ण राजनीति की जा रही है। व्यापार करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा समर्थित सरपंचों को धारा 40 के तहत बर्खास्तगी का डर दिखा कर कांग्रेस प्रवेश कराया जा रहा है। अब चुनाव को सिर्फ तीन ही माह बचे हैं।

भाजपा का मतलब विकास है

सांसद ने कहा कि, जनता भी चुनाव का इंतजार कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता फिर से भाजपा सरकार बनाएगी, क्योंकि भाजपा सरकार का मतलब विकास है। भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक साहू ने कहा कि मो. अकबर के नेतृत्व में कवर्धा के शांत राजनीतिक माहौल को बिगाड़ने का काम हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता इस सरकार को उखाड़ फेंकने व कवर्धा विधायक को हराने दिन रात काम कर रहे हैं।

18 को पंडरिया में प्रदर्शन

जनसभा के बाद कार्यकर्ता रैली निकाल कर विधायक कार्यालय का घेराव करने के लिए चल दिए। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश भी की। काफी नारेबाजी के बाद भाजपा नेताओं ने सरकार और क्षेत्रीय विधायक की विभिन्न नाकामियों को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अब इसी तहर18 जुलाई को पंडरिया में भी घेराव किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ आप की बदलाव यात्रा शुरू

22 जुलाई तक विधानसभाओं में फूंकेगी चुनावी बिगुल

रायपुर। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी आज बदलाव यात्रा का आगाज की। पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजीव झा आज प्रदेश के दौरे पर पहुंचें। वो 17 से 22 जुलाई तक कई जिलों में बदलाव यात्रा में शिरकत करेंगे। सोमवार को रायगढ़ के कनकुरी में बदलाव यात्रा का आगाज किया। इस दौरान अन्य कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे।

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी बिलासपुर में आयोजित महारैली के बाद पूरे प्रदेश में बदलाव यात्रा शुरू करने जा रही है। इसको लेकर प्रदेश सह प्रभारी एवं पंजाब के विधायक हरदीप सिंह मुंडिया ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि आप सभी ने मिलकर बिलासपुर में बहुत जबरदस्त महारैली का आयोजन किया। महारैली में प्रदेश के कोने-कोने से लोग शामिल हुए। इस महारैली से यहां स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और यह बदलाव की लहर चल चुकी है। आम आदमी पार्टी पूरी ताकत से प्रदेश में राजनीतिक बदलाव लाने जा रही है। यह बदलाव यात्रा प्रदेश के सभी विधानसभाओं के मुख्य बाजार में आयोजित की जाएगी। जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

बदलाव यात्रा विधानसभाओं के मुख्य स्थान से शुरू होगी

मुंडिया ने कहा कि बदलाव यात्रा बाजार के विधानसभाओं के मुख्य स्थान से शुरू होगी। बाजार के रास्तों से होते हुए पूरे बाजार को कवर करते हुए बाजार के ही दूसरे मुख्य स्थान पर खत्म होगी। उन्होंने बताया कि बदलाव यात्रा में प्रदेश प्रभारी संजीव झा समेत चारों सह प्रभारी अलग-अलग विधानसभाओं में शामिल होंगे। इस बदलाव यात्रा के जरिए हम अपनी जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आप प्रदेश प्रभारी संजीव झा 17 जुलाई को रायगढ़, 18 जुलाई को सरगुजा, 19 जुलाई को कोरबा, 20 जुलाई को कांकेर, 21 जुलाई को बस्तर और 22 जुलाई को राजधानी रायपुर में आयोजित बदलाव यात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान संजीव झा अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में बदलाव यात्रा के माध्यम से पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे।

मुख्यमंत्री का कलाकारों से मिलना भाजपा को नागवार गुजर रहा : कांग्रेस

■ **15 साल तक कलाकारों का शोषण करने वाले घड़ियाली आंसू मत बहाये**

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा राज्य के कलाकारों से मिलने पर भाजपाईयों द्वारा की गयी टिप्पणी को कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा की खीझ बताया है। 15 सालो तक छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा करने वाली भाजपा को कलाकारों की पूछ परख सम्मान पर पीड़ा हो रही है। प्रदेश की जनता और लोक कलाकार भूले नहीं है किस प्रकार रमन राज मे राज्योत्सव तक मे प्रदेश के बाहर के कलाकार बुलाये जाते थे। सलमान खान को अतिथि बना कर करोड़ो का भुगतान किया गया था करीना कपूर के एक मिनिट के ठुमके के लिए चार करोड़ का भुगतान किया गया था। छत्तीसगढ़ के कलाकारों से मिलने तक से परहेज करने वाले रमन सिंह चार करोड़ का भुगतान कर करीना कपूर के साथ सेल्फी खींच कर ट्विटर पर पोस्ट करते थे उनका पी आर विभाग विज्ञप्ति जारी करता था।

शुक्ला ने कहा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलाकारों से मिलकर उनकी मेजबानी करके राजधर्म निभाया है भाजपाई एक दृष्टांत बताये 15 साल के शासन काल मे कब रमन सिंह कलाकारों को बुला कर उनकी बात सुने हो उनके साथ समय व्यतीत किया हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कलाकारो के लिए विश्व आदिवासी नृत्य महोत्स्व जैसे आयोजन करवा कर अंतरास्ट्रीट मंच दिया अंतराष्ट्रीय रामायण महोत्स्व कौशल्या महोत्सव ने लोक कलाकारों का मान बढ़ाया मुख्यमंत्री निवास मे आयोजित तीज त्योहारों के कार्यक्रमों मे स्थानीय कलाकारों को सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता है। भाजपाइयों को बयानबाजी के पहले आत्मावलोकन करना चाहिए।

धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज

रायपुर। आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 18 जुलाई को होगी। यह बैठक छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित सभाकक्ष में दोपहर 1.30 बजे से आहूत की गई है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में मंत्रीगणों के अलावा कृषि, वित्त, राजस्व, सहकारिता, खाद्य विभाग के साथ ही छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन, चिप्स, अपैक्स बैंक और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों एवं फैसलों के कारण विगत चार सालों में किसानों की संख्या और रकबा में लगातार वृद्धि हुई है।

कांग्रेस का डीएनए ही डिफॉल्ट, सांप और छछूंदर दोनों पाल रही पार्टी : चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र मंगलवार से शुरु होगा। जिसमें बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। मॉनसून सत्र तीन दिनों का होगा। जिसमें पहले दिन, दिवंगत विधानसभा सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।वहीं इस सत्र में बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती।इस सत्र से पहले बीजेपी विधायक और प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है।

अजय चंद्राकर की माने तो सरकार के पास ईमानदारी से काम करने का कोई तरीका नहीं है। क्योंकि सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अभी तक कोई दृष्टि दिखाई नहीं देती है,सिवाय उनके विनियोग विधायक को छोड़ कर कोई दूसरी चीज नहीं आएगी। अगर कोई काम करना है तो 3 दिन के सत्र में बहुत संभव नहीं है।

अजय चंद्राकर ने कहा कि हम विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह करेंगे आखिरी सत्र है। बिना किसी समय निर्धारण के चर्चा करवाए। विधानसभा सत्र में जितने प्रश्न लगे हैं। उनमें चर्चा होगी।

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के सवाल को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि किसी के प्रदेश अध्यक्ष बनने या नहीं बनने से धर्म परिवर्तन की गति में कोई फर्क नहीं आएगा। असली फॉल्ट डीएनए में है। विपक्षी दलों की बैठक पर चंद्राकर ने कहा कि आज जो बैठक शुरू हो रही है,उसमें शिवसेना भी है और मुस्लिम लीग भी है। कांग्रेस का चिंतन ही विकृत चिंतन है। हमारी चिंतन की धारा स्पष्ट है। कांग्रेस सांप और छछूंदर दोनों को पाल रही है। ऐसे करके अपने आप को धर्म निरपेक्ष बताते हैं। लेकिन इनका डीएनए ही गलत है।

आरोप पत्र में हम झीरम पर भी लिखेंगे। किस तरह से कांग्रेस के लोग नक्सलियों के हाथों मारे गए। उनके भावनाओं के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैसे खिलवाड़ किया। इस सरकार के पास झूठ का पुलिंदा है। यह सरकार डिफॉल्टर है। यह सरकार कर्ज लेने वाली सरकार है।

किसानों के दुःख दर्द को हमने समझा और उसे दूर किया : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी ने बहुत सुंदर यहां मंच सजाया है। हरेली त्योहार हम सब उल्लास से मनाते हैं। हरेली त्योहार केवल गेड़ी चढने का त्योहार नहीं है। यह उत्साह का त्योहार है और इसके लिए वातावरण बनाना होता है और यह तब होता है , जब खुशहाली हो,किसान खुशहाल हो,हम यह सब कर रहे हैं। किसानों के दुख दर्द को हमने समझा। किसानों का रकबा बढ़ गया।

उन्होंने कहा कि अब 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। यह उल्लास का वातावरण सभी जगह है। आदिवासी क्षेत्रों में भी उल्लास का माहौल है।गोधन न्याय योजना के माध्यम से अर्थव्यवस्था सुधर रही है। दूध उत्पादन बढ़ गया है। हरेली में जो नीम की डाली का उपयोग होता है। वह कीटनाशक है। यह वर्षाजनित बीमारियों से बचाता है। किसान अपने उपकरणों की पूजा करते हैं। आज जिनके घर भी गाय है उनकी पूजा हो रही है। यही समृद्धि का रास्ता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल आरम्भ किये। इससे बड़ी संख्या में लोगों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी शिक्षा मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों द्वारा बरसों से तैयार की गई हमारी संस्कृति नष्ट हो रही थी। इसे संरक्षित करने का प्रयास हमने किया है और बहुत बढ़िया काम हो रहा है। रामायण के माध्यम से हम लोगों के जीवन में भगवान राम का आदर्श उतारने की कोशिश कर रहे हैं। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव किया। चंदखुरी, शिवरीनारायण और राजिम के साथ ही राम वनगमन पथ को विकसित करने का हमने कार्य किया है।

बस्तर में देवगुड़ी को संरक्षित किया गया। घोटुल का संरक्षण किया। आसना में बादल आरम्भ किया गया। इससे बस्तर की लोक संस्कृति को सहेजने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमारे आदिवासी जीवन की परंपरा बहुत समृद्ध रही है। इतनी सुंदर परम्परा है जिन्हें हम सोचें तो चकित हो जाते हैं। यह ऐसी संस्कृति है जो अपने देवी-देवताओं के साथ रहती है। उनसे गहन लगाव रखती है। इसके लिए हमने कार्य किया।जो मजदूरों किसानों का भोजन बोरे-बासी है वो अब फाइव स्टार होटल तक पहुंच गया है। अपनी संस्कृति पर हम सब गौरव करते हैं। जो लोग हीनताबोध में थे वे इस संस्कृति के गौरव को महसूस कर रहे हैं और छत्तीसगढिया सबले बढिया वाक्य को चरितार्थ कर रहे हैं।

सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का किया शुभारंभ

सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी शुभारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत सीएम भूपेश ने गेड़ी चढ़कर और भंवरा चलाकर किया। इस बार ओलंपिक में 16 खेलों को शामिल किया गया है। जिसमें बांटी, गिल्ली डंडा, मटकी फोड़ और गेड़ी नृत्य सहित कई छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने रहचुली का भी मजा लिया। किसान अगर खुशहाल होगा तो तभी असल मायने में हरेली तिहार सार्थक होगा। हमारी सरकार लगातार किसानों को खुशहाल करने प्रयास कर रही है। हमारी नीति किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हैं। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। सीएम भूपेश ने हरेली तिहार के मौके पर प्रदेशवासियों से कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की है। साथ ही पौधरोपण के साथ ली हुई फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करने को भी कहा है।

सीएम दिखावा ना करें, हरेली पर्व छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराः साव

■ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर में मनाया हरेली तिहार

रायपुर। जिला भाजपा द्वारा जिलाध्यक्ष जयंती पटेल के नेतृत्व में रायपुर के पुराना आमानाका थाना के पास मथुरा नगर गौठान में जाकर हरेली तिहार मनाया गया। भगवती चरण शुक्ल वार्ड में आयोजित कार्यक्रम में विशिष्ठ रूप से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव उपस्थित पधारे

गौठान के पास स्थित राधाकृष्ण मंदिर में पहले पूजा अर्चना की गई तत्पश्चात हरेली में खेले जाने वाले पारंपरिक खेलो को खेला गया स्थानीय महिलाओं सहित महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा खो-खो , कुर्सीदौड़ , फुगड़ी जैसे अन्य पारंपरिक खेल खेले गए, तो वहीं स्थानीय पुरुषों सहित भाजपा नेताओ द्वारा कबड्डी , भौरा और गेड़ी चढ़ा गया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने हरेली में उपयोग की जाने वाली पारंपरिक गेड़ी की पूजा की तत्पश्चात कृष्ण मंदिर एवं जैतखंभ में नारियल अगरबत्ती से पूजन किया आयोजित की गई पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरुस्कृत किया गया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा की छत्तीसगढ़ तिहार का प्रदेश है हरेली हमारा पहला तिहार है प्रकृति के प्रति असीम समर्पण और आदर के भाव को दर्शाने आपसी प्रेम सौहाद्र बढ़ाने का संदेश देता है हरेली तिहार घरों घर गुलगुला ठेठरी भजिया जैसे पकवान बनाएं जाते हैं पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जाता है बारिश का रमणीय मौसम और कीचड़ में गेड़ी चढ़ने का अपना ही आनंद है हम सभी मिलकर श्रावण के इस पावन पर्व पर महादेव से छत्तीसगढ़ प्रदेश सहित समग्र संसार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं ।

भाजपा वरिष्ठ नेता ,पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा की गेड़ी चढ़ते वक्त बचपन के दिनों की यादें ताजा हो जाती है तब मोबाइल नहीं हुआ करता था और हम सभी गेड़ी , भौरा और गिल्ली डंडा जैसे परंपरागत खेलो को खेला करते थे आज यहां आयोजित किए गए खेलों में अपनी मिट्टी की महक है अदभुत अपनेपन का भाव है मैं आज हमारे छत्तीसगढ़ के पहले तिहार प्रकृति के प्रति अपने समर्पण के तिहार हरेली पर भगवान से मानव कल्याण और प्राकृतिक संतुलन की कामना करता हूं ।

जिला रायपुर अध्यक्ष जयंती पटेल ने कहा की हरेली तिहार में परम्परागत खेलो का आयोजन अपनी परंपराओं और संस्कृति को संजोए रखने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया गया हम निरंतर ऐसे प्रयास आगे भी करते रहेंगे ।

आज मथुरा नगर गौठान में आयोजित किए गए हरेली तिहार में विशेष रूप से पूर्व विधायक द्वय श्रीचंद सुंदरानी , नंदकुमार साहू , केदार गुप्ता , संजय श्रीवास्तव , अशोक पांडेय , प्रफुल्ल विश्वकर्मा रमेश सिंह ठाकुर सत्यम दुआ प्रफुल विश्वकर्मा , ललित जयसिंघ , आशु चंद्रवंशी , गोपी साहू , अमित मैशरी ,खेमकुमार सेन , सुभाष अग्रवाल , वंदना राठौड , सीमा संतोष साहू , राजियंत ध्रुव , नवीन शर्मा , अनिल सोनकर , भूपेंद्र ठाकुर अर्चना शुक्ला, गोविंदा गुप्ता नीलम सिंह पुरुषोत्तम देवांगन कामिनी देवांगन ,राहुल राव , अर्पित सूर्यवंशी सहित बड़ी संख्या में जिला भाजपा पदाधिकारियों सहित स्थानीय जवान , महिला , सियान उपस्थित थे ।

उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने ऊर्जा विभाग की ली लंबी बैठक

रायपुर । उपमुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने ऊर्जा विभाग का कार्यभार संभावलने के बाद तीन घंटे से अधिक की लंबी बैठक ली। उन्होंने प्रदेश में विद्युत उत्पादन और आपूर्ति की जानकारी ली और भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उत्पादन, पारेषण और वितरण की क्षमता बढ़ाने की दिशा में योजना बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आ रही नई तकनीक को अपनाते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति की दिशा में काम करने पर जोर दिया। श्री सिंहदेव ने साप्ताहिक एवं पाक्षिक बैठकें लेकर प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाफ बिजली बिल योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए।

न्यू सर्किट हाउस में आयोजित लगभग साढ़े तीन घंटे चली बैठक में ऊर्जा विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज, क्रेडा, राज्य विद्युत निरीक्षालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ऊर्जा सचिव एवं पॉवर कंपनी के चेयरमेन श्री अंकित आनंद ने उनका स्वागत किया और विभाग की विस्तार से जानकारी दी। उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने सभी अधिकारियों से व्यक्तिगत परिचय प्राप्त किया। उन्होंने ट्रांसमिशन और जनरेशन कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहतर होने पर खुशी जताई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े होने के कारण वितरण कंपनी का कार्य अपने आप में चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बिजली बिल हाफ योजना से उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होंने कोरबा में प्रस्तावित 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट के बारे में जानकारी ली। साथ ही पानी का कई बार उपयोग करके पंप स्टोरेज तकनीक से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं पर काम करने के निर्देश दिये। उपमुख्यमंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि लाइन लास पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। इसे और कम किया जाए ताकि इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिले। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि किसी उपभोक्ता को अधिक बिल दे दिया जाता है, तो उसकी जाँच करने की व्यवस्था करें। इसका ध्यान रखें कि ऐसी मुस्तैदी के बिलिंग की जाए कि इस तरह की शिकायतें न आए। पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की प्रबंध निदेशक श्रीमती उज्जवला बघेल, पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री एसके कटियार एवं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री मनोज खरे ने विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण प्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 62 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस साल अधिकतम मांग 5869 मेगावाट अप्रैल में थी।

मेरी बात

✍ गिरीश पंकज

चैटजीपीटी साहित्य!

चैटजीपीटी समाज की मौलिक प्रतिभा का, उसके चिंतन को नष्ट करने का एक ऐसा नया माध्यम है, जिसका दुष्परिणाम अब नज़र आने लगा है। अनेक नए लड़के इसके सहारे कविताएं कर रहे हैं। किताबें भी छपवा रहे हैं। अब होगा यही कि जो साधक हैं, वे किनारे हो जाएंगे और जो नकलची हैं, वे छाए रहेंगे। पिछले दिनों मैंने गूगल में जा कर चैटजीपीटी को खोला और वहाँ लिखा माँ पर कविता लिखे, तो मेरे सामने आ गई यह कविता। देखिए इसे, जगत की राजमाता है, माँ कहलाती है, प्रेम की योति जगाती है, माँ कहलाती है।जन्म से ही आशीष देती है, माँ कहलाती है, हर दुःख को दूर भगाती है, माँ कहलाती है।मुसीबतों के सामने खड़ी होती है, माँ कहलाती है, अपने बचों को समर्पित होती है, माँ कहलाती है।ममता की आग जलाती है, माँ कहलाती है, सबको गोद में ले जाती है, माँ कहलाती है।उनकी ममता अपार है, माँ कहलाती है, हर दिन का त्योहार है, माँ कहलाती है।

दुःख सुख के साथ खड़ी रहती है, माँ कहलाती है, खुशियों के अंगार बन जाती है, माँ कहलाती है।

जगत की राजमाता है, माँ कहलाती है, प्रेम की योति जगाती है, माँ कहलाती है।माँ, तुम हो ममता की देवी, तुम्हारे बिना ये जग सूना है बेवकूफी। तुम्हारी एक झलक पर हम सब वारी,

माँ, तुम हो हमारी दुनिया की अपारी।

चकित हूँ मैं। सोचिए, यह माध्यम हमारी मौलिकता के लिए कितना बड़ा खतरा है! न जाने कितने ही भ्रष्टाचारी, खा -पीकर अघाये बुद्धिहीन, चोर लोग भी आने वाले समय में कवि बन जाएंगे। शायद बन भी रहे हों! उनकी पुस्तकें भी छप जाएँ। चैटजीपीटी की मदद से कोई कविता बनी है, किसे पता चलेगा? यह और बात है कि उसकी आत्मा उसे धिक्कारेगी। अगर वह होगी तो! अफसोस! चैटजीपीटी पर आप भी माँ पर कविता टाइप करके देखें। एक कविता आ जाएगी। हालांकि पूरी कविता पढ़ कर समझ में आ जाता है कि कविता किसी व्यक्ति ने नहीं, सचमुच चैटजीपीटी ने ही लिखी है। अंत में जैसे बेवकूफी, अपारी,खुशियों के अंगार देखें। जैसे शब्द और वाक्य हैं जो एकदम असंगत हैं। वाक्य विन्यास भी कहीं-कहीं सही नहीं है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करूँगा कि वह कविता, कहानी या साहित्य की किसी भी विधा में लिखने के लिए चैटजीपीटी की मदद न लें, वरना उनका मौलिक चिंतन नष्ट हो जाएगा। आप मानसिक विकलांगता के शिकार हो जाएँगे। आप अन्य क्षेत्र में सूचनाओ को प्राप्त करने के लिए

चैटजीपीटी का उपयोग कर सकते हैं लेकिन साहित्य रचना के लिए अपनी मौलिक विधा का इस्तेमाल करें। इस से सृजन का संतोष होगा। मन में अपराध बोध नहीं होगा। रचना को देखेंगे तो यह सोच कर ग्लानि नहीं होगी कि जो कुछ मैंने लिखा है मेरा नहीं है, चैटजीपीटी का माल है।

वैसे चैटजीपीटी द्वारा लिखी जाने वाली नई कविता को ठीक-ठाक करके कोई फर्जी लेखक अपने नाम से प्रकाशित भी कर सकता है, लेकिन चाहे तकनीक इतनी भी आगे बढ़ जाए, मशीन छंदबद्ध रचना कभी नहीं कर सकती । न दोहा लिख सकती है, न चौपाई रच सकती है। मैंने परीक्षण हेतु चतजीपीटी के बॉक्स में टाइप किया कि चौपाई लिखें, तो निम्न रचना सामने प्रकट हुई, जबकि यह कहीं से चौपाई नहीं है। देखें , राम नाम आदर्श है, धर्म का सार जीवन में। जन्म लेते हैं श्रेष्ठ वन में, धन्य हैं राम की योगिनी। यह किसी भी कोण से चौपाई नहीं है। चौपाई की एक अर्धाली में सोलह मात्राएँ होती हैं। दूसरी में भी सोलह होती हैं।दोहे में पह अर्धाली में तेरह और दूसरी में ग्यारह मात्राएँ होती हैं। दूसरी पंक्ति में भी तेरह ग्यारह मात्राएँ होती हैं। इसी तरह गीत हैं, कुंडलियाँ हैं, सोरठा है। अनेक छंद है। विज्ञान जितनी भी तरक्की कर ले, मानव मन की कोमल भावनाओ को आत्मसात करके वह छंद नहीं रच सकता। हाँ, नई कविता तो लिखी जा सकती है जिसमें छंद का अनुशासन ज़रूरी नहीं होता। चैटजीपीटी जैसी भटकाव वाली असंगत सी कविताएँ हिंदी के अनेक तथाकथित कवि वर्षों से लिख रहे हैं। इस कारण कविता अलोकप्रिय भी हुई। चैटजीपीटी के कारण अब कविता का और कबाड़ा होगा। यानी साहित्य का।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षताः नए भारत की विकास गाथा

रायपुर। भारत आज विकास की ऊंची उड़ान भरने को तैयार है। वैश्विक स्तर पर सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक्स संबंधी रेटिंग बेहतर होते जाने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स से जुड़ी इसकी बाधाएं दूर होती जा रही हैं। मैन्यूफैक्चरिंग और व्यापार के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति बुनियादी ढांचे और निर्यात-आयात संबंधी लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने से संबंधित सुधारों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। बुनियादी ढांचे को अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण विकास इंजन के रूप में पहचानते हुए, प्रधानमंत्री की गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसे सुधारों ने सामानों एवं यात्रियों की आवाजाही के लिए लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स संबंधी सेवाओं में सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया है। और बहुत ही कम समय में, इन सुधारों के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) से संबंधित 2023 की अपनी रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी उन्नत दक्षता की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार किया है।

दम है तो हमारे आरोप पत्र पर बनाएं कमेटीः चंद्राकर

रायपुर। आरोप पत्र समिति की बैठक और आरोप पत्र तैयार करने की बात पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, एक झलकी देते हैं, 8 करोड़ रुपए के डैम बिना काम और टेंडर के बन गए. पैसा भी निकल गया और टेंडर भी नहीं बना. यदि सरकार में दम है तो हमारे आरोप पत्र पर वह कमेटी बनाएं. जिस दिन जारी करेंगे उस दिन जांच स्वयं करवाएंगे. हम झीरम पर भी पत्र में लिखेंगे.चंद्राकर ने कहा, शराबबंदी घोषित है. धान खरीदी और कर्ज माफी के लिए कसम खाएं हैं बोलते हैं. जो वह बोले सब सही, जो हम बोले वह सब गलत. आपको बताना था कि गंगाजल की सौगंध किस किस चीज के लिए खाई है.

विधानसभा मानसून सत्र को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, 3 दिन का सत्र रहेगा. परंपरा अनुसार सत्र दिनभर के लिए स्थगित हो जाएगा. बीजेपी का या विधानसभा का सबसे बड़ा मोशन नोङ्कॉन्फिडेंस मोशन है, जिसे हमने मोशन में भेज दिया है. सरकार को ईमानदारी से काम करना है. उनकी कोई दृष्टि नहीं है, कोई विजन नहीं है. विनियोग विधेयक को छोड़कर कुछ नहीं आएगा. अन्य कामों को करने के लिए तीन दिन के सत्र में संभव नहीं है. हम अध्यक्ष से आग्रह करेंगे की खुली चर्चा बिना किसी समय निर्धारण के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करवाएं.पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तीन दिनों में सभी प्रश्नों के उत्तर देने की बात पर कहा, जितने प्रश्न लगे हैं उतने होंगे. तीन दिनों के सरकारी बिजनेस का सवाल है. सरकार दिशाहीन हो गई है. गिल्ली डंडा और भौंरे में लगी रहेगी. सरकार की जनकल्याण के लिए कोई विषय है या नहीं.हरेली पर्व पर सरकार द्वारा खुद को किसान हितैषी बताए जाने को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है. उन्होंने कहा, संस्कृति क्या है. यह हमें राज्य सरकार से जानने की जरूरत नहीं है. देश के पूरे क्षेत्रों में भौगोलिक संस्कृति के बहुत सारे आयाम हैं. हरेली से कम नहीं है दुर्ग और कुरूद में जो घटना घटती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भूपेश बताएं कहां उड़ा रहे हैं मिलने वाली रकमः केदार

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महामंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि डिब्बे बदल देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का इंजन ही खराब है। यह गाड़ी अब चलने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में यह कंडम गाड़ी यार्ड में पहुंच जाएगी। कांग्रेस लगातार भ्रम फैला रही है कि जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा। हम पूछते हैं कि जो पैसा मिल रहा है, वह किस मद में खर्च कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है और उनके जाते ही कहते हैं कि सहयोग नहीं मिल रहा। यही बात कांग्रेस के अध्यक्ष ने कही है। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पलटी क्यों मारती है। खुद को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री किसानों को खाद नहीं दिला सकते।कांग्रेस आदिवासी समाज का अपमान कर रही है। जिन नंदकुमार साय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने बैठाकर चर्चा करते थे, जिन वरिष्ठ नेता को भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा, लोकसभा सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने उन्हें अब तक का सबसे छोटा पद टिका कर आदिवासी समाज को शर्मिंदा किया है। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने 11 जुलाई तक 2 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।

किसानों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 16.29 करोड़ रूपए की दी सौगात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज 17 जुलाई को हरेली तिहार के अवसर पर गौठानों में गोबर बेचने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों सहित गौठान समितियों और महिला समूहों को 16 करोड़ 29 लाख रूपए की राशि का अंतरण सीधे उनके बैंक खातों में किया। गोधन न्याय योजना के तहत ऑनलाईन राशि अंतरण का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हरेली तिहार उत्सव के अवसर पर आज शाम आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इनमें जुलाई माह की प्रथम पखवाड़े में गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले 59,729 किसानों को 3 करोड़ 96 लाख रूपए तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 12 करोड़ 33 लाख रूपए की राशि जारी किया। गौठानों में जुलाई माह के प्रथम पखवाड़े में एक लाख 98 हजार क्विंटल गोबर की खरीदी गोधन न्याय योजना के तहत की गई है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत आज 17 जुलाई को 16.29 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद हितग्राहियों को अब तक 526.37 करोड़ रूपए का भुगतान हो चुका है।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरेली तिहार को रोजगार और आय से जोड़ते हुए गोधन न्याय योजना की शुरूआत हरेली के ही दिन 20 जुलाई 2020 को हुई थी। आय यह योजना अपनी सफलता के लिए एक नजीर बन चुकी है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने 2 रूपए किलों में गोबर खरीदकर उससे जैविक खाद का निर्माण किया, बिजली बनाई, प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया।

संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी भाजपाः चंदेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आंदोलन कर रहे संविदा कर्मचारियों के बीच जाकर उनकी मांग का समर्थन करते हुए ऐलान किया कि भाजपा की सरकार बनने पर निश्चित रूप से उनकी मांग पूरी की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष श्री चंदेल ने बरसात के बीच धरने पर बैठे हजारों कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में भाजपा आपकी मांग को पूरी ताकत के साथ उठाएगी।नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कर्मचारियों के आंदोलन स्थल पहुंचकर इन कर्मचारियों को समर्थन देते हुए कहा कि हरेली के पावन दिन आप हड़ताल पर बैठे हैं और यह लबरा भूपेश बघेल सरकार के कारण यहां बैठे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन में आप सबके सामने आपका समर्थन करने आया हूं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आपके बीच आकर आप की मांग का समर्थन कर चुके हैं। मैंने सारे नेताओं से चर्चा की है कि मैं आपके बीच समर्थन देने जा रहा हूं। सभी ने कहा कि हमारी ओर से आश्वस्त कर दें कि तीन महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमल छाप भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र बनेगा उसमें कर आपके नियमितीकरण की घोषणा होगी।

अपने गिरेबान में झांककर देखें, भाजपा : अमरजीत भगत

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि, भाजपा वालों के मुंह में दांत नहीं है, इसलिए वह कुछ भी बोलते हैं। उनकी जुबान फिसल जाती है। वह अपने गिरेबान में झांककर देखें। अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जो आदिवासी समाज के हैं, उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही पद से हटा दिया। क्या यह शोभा देता है? क्या आदिवासी समाज इसे सहन करेगा? कांग्रेस के मंत्रियों के प्रभार बदलने के मामले में पूछे गए सवाल पर मंत्री भगत जवाब दे रहे थे। वह एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव पहुंचे थे। आदिवासी सीएम की मांग को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि प्रदेश के विकास करने के लिए मुख्यमंत्री का आदिवासी ही होना आवश्यक नहीं है। आपका दृष्टिकोण, आपका समर्पण, आप क्या कर रहे हैं? काम की समीक्षा होती है। मुख्यमंत्री भले आदिवासी नहीं है, लेकिन आदिवासियों का जो भी मुद्दा आया है, उतनी तत्परता और गंभीरता के साथ निराकरण किया है। पिछली सरकार में आप लोगों ने देखा है डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, सबको सेंट्रलाइज करके रखा था। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार काम हुए हैं। सरगुजा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रमन सिंह हुआ करते थे। हमारे भूपेश बघेल ने आदिवासी सीनियर नेता को अध्यक्ष बनाया है। प्रदेश सरकार लगातार आदिवासियों के हित में कार्य कर रही है। इससे पहले उन्होंने शहर के कमला कॉलेज चौक के पास स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण किया।

टीचर भर्ती में अब आरक्षण का विवाद पहुंचा हाईकोर्ट

बिलासपुर। प्रदेश में चल रही टीचर भर्ती प्रक्रिया में अब आरक्षण का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसके साथ ही केस के फैसले से नियुक्ति प्रक्रिया को बाधित रखा है।कामेश्वर कुमार यादव, योगेन्द्र मनी वर्मा सहित अन्य ने अपने एडवोकेट के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि राज्य शासन ने शिक्षक के टी-संवर्ग के 4 हजार 659 एवं ई- संवर्ग के 1 हजार 113 पदों की भर्ती के लिए चार मई को विज्ञापन जारी किया है। इसमें सहायक शिक्षक पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है।याचिका में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1994 के तहत तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग पदों के लिए अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है।भर्ती प्रक्रिया में राज्य शासन ने अनुसूचित जनजाति को 65 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे दिया है। राज्य शासन का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर कहा है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2011 में 50 से 58 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाने की अधिसूचना को भी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

असौंदा में शराब विरोधी मोर्चा का असर, खुले आम बिक्री रुका

रायपुर । मुख्य सड़क मार्ग सहित ग्राम के गली कूचों में बिक रहे अवैध शराब के खिलाफ असौंदा के ग्रामीणों द्वारा खोले गये मोर्चा के बाद शराब न बेचने के कोचियो के आश्वासन के चलते उन पर निगरानी के निर्णय के साथ स्थगित आंदोलन के एक सप्ताह बीतते - बीतते बीते 17 जुलाई को समीक्षा बैठक संपन्न हुई । बैठक में ग्रामीणों ने खुले आम अवैध शराब बिक्री रुक जाने पर गुपचुप शराब बिकने की बात कही । इस शराब बिक्री के? पीछे ग्राम के ही निवासी एक शराब सप्लायर व उसके एक रिश्तेदार की प्रमुख भूमिका होने की जानकारी दी । बैठक में आंदोलन में प्रमुख भूमिका निबाहने वाली एक महिला से इसी शराब

सप्लायर द्वारा मोबाइल नंबर मांगने के बाद अलग-अलग नंबरों से अनर्गल काल आने की जानकारी इस महिला ने सार्वजनिक तौर पर दी । ग्रामीणों ने वादाखिलाफी करने वाले कोचियो के साथ महिला को अनर्गल काल करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने थाना प्रभारी से ले एस पी तक शिकायत करने व कुछ दिनों बाद पुनः समीक्षा बैठक कर रणनीति बनाने का निर्णय लिया । ज्ञातव्य हो कि अवैध शराब बिक्री से त्रस्त ग्रामीणों ने बीते 2 जुलाई को इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था जिसके चलते कोचियो द्वारा अवैध शराब बिक्री से तौबा कर लेने के आश्वासन के बाद बीते 11जुलाई को इन पर निगरानी रखने व कुछ समय बाद समीक्षा बैठक करने के निर्णय के साथ आंदोलन पर अस्थायी रुप से विराम लगा दिया था। बैठक में ग्राम के ही निवासी एक कथित बैठक शराब सप्लायर द्वारा आश्वासन के बाद भी अपने एक रिश्तेदार व? कतिपय नाबालिगों के माध्यम से ग्राम में गुपचुप तरीके से शराब बिकवाने का आरोप लगाया गया । आंदोलन में महती भूमिका निबाहने वाली महिला ने इस शराब सप्लायर द्वारा मोबाइल नंबर लेने के बाद से लगातार अलग अलग नंबरों से अनर्गल काल आने की जानकारी दी व इस सप्लायर से पूछने पर इसमें उसका कोई भूमिका न होने व ग्रामीण बैठका में यह जानकारी न देने की धमकी दी । इस बैठक में इस शराब सप्लायर व शराब बेचने वाले उसके रिश्तेदार को इसकी पुष्टि करने व समझाईश देने बुलाया गया पर वे ग्राम से बाहर होने की? बात कह कन्नी काट गये। इस शराब सप्लायर व ग्राम के अवैध शराब विक्रेताओं की पूरी जानकारी आबकारी व थाना प्रशासन को होने व इन पर रोक लगाने में कोताही बरतने का?आरोप लगाते हुये ग्रामीणों ने थाना प्रभारी से ले एस पी को ज्ञापन सौंपने व क्षेत्रीय विधायक श्रीमती अनिता शर्मा को? भी इसकी जानकारी देने का निर्णय लिया।

छत्तीसगढ़ को मिलेगा राष्ट्रपति के हाथों भूमि सम्मान

रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान मिलेगा। साथ ही प्रदेश के दो जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा।मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए है, जिससे आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां मिलना आसान हुआ है।गौरतलब है कि डिजिटल इंडिया लैण्ड रिकार्ड मॉर्डनाईजेशन प्रोग्राम अंतर्गत प्रदेश में भूमि प्रबंधन से जुड़े 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी तरह भूमि प्रबंधन से जुड़े चार घटकों, लैण्ड रिकार्ड का डिजिटाइजेशन, पंजीयन कार्यालय से समन्वय, मॉडल रिकार्ड रूम की स्थापना में प्रदेश के सरगुजा और बेमेतरा जिले में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.